



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रामाणिकर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1991/ज्याइस्था 10, 1913

No. 205]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1991/JYAISTHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न एक संख्या की जाती है जिससे कि वह अपने संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1991

सा.वा.नि. 291 (अ).--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 108 की उप-धारा (6) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड अधिनियम निम्नलिखित विनियमों को निर्मित करता है, नामशः--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ एवं व्याख्या :--(1) इन विनियमों का नाम कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) सामान्य वाक्य अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में उसी प्रकार लागू होना है जिस प्रकार वह किसी केंद्रीय अधिनियम की व्याख्या में लागू होता है।

2. परिभाषाएं :--(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

(ख) "अनुलग्नक" का अर्थ है इन विनियमों का अनुलग्नक

(ग) "आवेदन पत्र" का अर्थ है ऐसा आवेदन पत्र जिसके द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई एक ग्यायपीठ के समक्ष प्रारम्भ होती है।

(घ) "अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई पक्षकार ने विनियम 191 के उप नियम (2) के अन्तर्गत अपने प्रतिनिधि के रूप में ग्यायपीठ के समक्ष लिखित रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया हो।

(ङ) "ग्यायपीठ" का अर्थ है अधिनियम की धारा 108 की उप धारा (4ख) के अन्तर्गत गठित बोर्ड की एक ग्यायपीठ।

(च) "ग्यायपीठाधिकारी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा निम्न अधिप्रायों के लिए अधिसूचित अधिकारी :--

(i) आवेदन पत्र प्राप्त करने, उनकी परीक्षा करने और उन पर कार्यवाई जारी करने के लिए

(ii) इन विनियमों के द्वारा या उनके अन्तर्गत जो अन्य कार्य सोये जायें उन्हें करने के लिए।

(छ) "बोर्ड" का अर्थ है अधिनियम की धारा 108 के अन्तर्गत गठित कम्पनी विधि प्रशासन का बोर्ड।

(ज) एक प्रति के संबंध में

"प्रमाणित का अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 78 के अन्तर्गत जैसा प्रावधान किया गया है उस प्रकार प्रमाणित।

(झ) "अध्यक्ष" का अर्थ है कम्पनी का बोर्ड का अध्यक्ष।

(ञ) "कम्पनी" में एक विदेशी कम्पनी शामिल है।

(ट) "वांछित किया" का अर्थ है पीठ के कार्यालय में वांछित किया हुआ।

(ठ) "कार्य" का अर्थ है अनुसूचक II में निर्दिष्ट कार्य।

(ड) "सदस्य" का अर्थ है बोर्ड का सदस्य।

(ढ) "एकाधिकार अधिनियम" का अर्थ है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54)।

(ण) "पीठ का कार्यालय" का अर्थ है पीठाधिकारी का कार्यालय।

(त) "पक्ष" का अर्थ है वह व्यक्ति जो पीठ के समक्ष आवेदन पत्र या याचिका दायर करता है, प्रतिपक्षी, कम्पनी रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय निदेशक और उसमें से लोग भी शरीक हैं जो सुझाव देते हैं या आपत्ति करते हैं।

(थ) "याचिका" का अर्थ है एक आवेदन पत्र, अपील या शिकायत जिसके कारण कोई कार्यवाही जो अन्तर्वादी कार्यवाही न हो, पीठ द्वारा प्रारम्भ की जाती है।

(ब) "हवाले" का अर्थ है इन विनियमों के विनियम 35, 40 और 42 के अन्तर्गत्तु किया गया हवाला।

(ख) "क्षेत्रीय निदेशक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अधिप्राय के लिये क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया है।

(न) "रजिस्ट्रार" का अर्थ है अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कंपनियों का रजिस्ट्रार।

(य) "सुहरबन्द" का अर्थ है बोर्ड या पीठ की सेवा द्वारा सुहरबन्द।

(र) "सचिव" का अर्थ है बोर्ड का सचिव और इसमें बोर्ड के "अवर सचिव" और अन्य अधिकारी जिन्हें विनियम 31 के अन्तर्गत सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य सौंपे जाय।

(ल) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की एक धारा।

(व) "प्रतिभूति अधिनियम" का अर्थ है प्रतिभूति करार (नियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)।

(2) इन विनियमों में प्रकट होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें उप विनियम (1) में परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ रखेंगे जो अधिनियम में हों।

अध्याय-II

सामान्य

3. बोर्ड की पीठ का संघटन :- (1) विनियम 4 का शर्तों के तहत, अधिनियम की धारा 108 का उप-धारा (4ख) के अन्तर्गत गठित बोर्ड की प्रत्येक पीठ में एक से अधिक सदस्य होंगे।

(2) अध्यक्ष द्वारा किसी भी न्याय पीठ के गठन का आदेश उन शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करेगा जिनका प्रयोग और सम्पादन पीठ द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रत्येक गठित न्याय पीठ के संबंध में, अध्यक्ष पीठ के उस सदस्य का उल्लेख करेंगे जिनके समक्ष बोर्ड के आदेश का अपेक्षा रखने वाले प्रत्येक मामले रखे जायेंगे। जो याचिका पर अन्तिम फैसले से संबंधित आदेश न होगा। और इस प्रकार उल्लिखित सदस्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार का प्रत्येक मामला पीठ के किसी अन्य सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो उपस्थित होगा।

4. एक न्यायपीठ द्वारा निपटार्य जाने वाले मामलों को निर्दिष्ट करने के बारे में अध्यक्ष की शक्ति :

(1) अध्यक्ष के लिए इस बात का प्रावधान करना विधि संगत होगा कि धारा 235, 237, 247, 248, 250, 388 ख, 408 और 409 के अन्तर्गत आने वाले मामले और अधिनियम के भाग 6 के अध्याय 4 के अन्तर्गत आने वाले मामले और एकाधिकार अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत आने वाले मामले और इनसे संबंधित भारत मानव प्रशासन में दो से कम सदस्यों की पीठ द्वारा नहीं देखे जायेंगे (जिसे मुख्य पीठ के नाम से जाना जायेगा)।

(2) मुख्य पीठ नई दिल्ली में होगी परन्तु मुख्य न्याय पीठ भारत में ऐसे स्थानों में और ऐसे समय बैठ सकती है जो भारत में इसकी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के संपादन में सर्वाधिक सुविधाजनक हों।

(3) अध्यक्ष के लिए यह प्रावधान करना विधि संगत होगा कि अधिनियम की धारा III और 269 तथा प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22क के अन्तर्गत आने वाले मामले ऐसी न्याय पीठ द्वारा देखे जायेंगे जिसमें दो से कम सदस्य न होंगे और इन विनियम के उप विनियम (1) और (2) के अन्तर्गत न आने वाले अन्य सभी मामलों जिनमें निर्देशों का जारी करना और अन्तर्वादी मामले शामिल होने एकत्र सदस्य वाली पीठ द्वारा देखे जा सकते हैं।

5. अध्यक्ष के पद की रिक्तता :- यदि किसी कारणवश अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होता है या उनका पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाना है तो बोर्ड का वरिष्ठतम सदस्य, कुछ समय के लिए अध्यक्ष का पद धारण करते हुए अध्यक्ष के कार्य का सम्पादन तब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त न हो जाये, करता रहेगा।

6. अध्यक्ष का कार्य संपादन की अवस्था :- जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से अपने कार्य का संपादन करने में असमर्थ हो तो बोर्ड का वरिष्ठतम सदस्य, यदि उसे अध्यक्ष द्वारा ऐसा अधिकार दिया जाये, अध्यक्ष के कार्य का सम्पादन उस दिन तक करता रहेगा जिस दिन अध्यक्ष पुनः कार्य भार ग्रहण कर लेंगे।

7. पीठ का क्षेत्राधिकार :- (1) समस्त कार्यवाहियाँ, मुख्य पीठ के समक्ष विनियम 4 के अन्तर्गत कार्यवाहियों के अतिरिक्त, उस पीठ के समक्ष दायर की जायेंगी जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(2) वे क्षेत्र जहाँ न्यायपीठ साधारणतया अपनी बैठकें करेंगी उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र हैं जिनके अन्तर्गत आने वाले राज्य और संघ क्षेत्र वे राज्य और संघ क्षेत्र हैं जिन्हें इन विनियमों के अनुसूचक 1 में दर्शाया गया है।

(3) साधारणतया पीठें अपनी बैठकें कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्र), बम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) मद्रास, (दक्षिणी क्षेत्र) और नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र) में करेंगी।

बशर्त कि पीठ अपनी बैठकें उस क्षेत्र में आने वाले किसी भी नगर या कस्बे में कर सकती है।

8. पीठ की भाषा

(1) पीठ की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी में की जाएगी।

(2) कोई भी याचिका, आवेदन पत्र, हवाल्ला, दस्तावेज या अन्य सामान अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में बोर्ड द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ उसका अंग्रेजी या हिन्दी में सत्य अनुवाद साथ-साथ न दिया गया हो।

(3) हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद की ओर रूखने वाले सभी दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा नियुक्त या अनुमोदित व्यक्ति द्वारा अनुवाद किया जाएगा।

बशर्त कि ऐसा कोई भी अनुवाद जिस पर कार्यवाही में संलग्न पक्ष सहमत हो बोर्ड द्वारा उचित प्रकरणों में स्वीकार किया जा सकता है।

(4) पीठ के समस्त अंतिम या अन्तर्वादी आदेश अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे।

9. अध्यक्ष द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष आदेशों की शर्तों के अन्तर्गत पीठ की बैठक के बड़े सिवा रविवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों के समस्त कार्य दिवसों पर 10.30 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न और 2.30 अपराह्न से 4.30 अपराह्न तक होंगे।

10. पीठ की अपनी मुहर होगी। (1) बोर्ड की पीठ की एक प्रतिलिपि भोहर होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक भोहर सचिव या पीठाधिकारी की सुरक्षा में रखी जाएगी और उसके निदेश और नियंत्रण में उक्त उपयोग होगा।

(3) प्रत्येक किया गया आदेश या पत्र जारी की गई सूचना या एक पीठ द्वारा मंजूर की गई प्रमाणित प्रति सम्बन्धित पीठ की मुहर की छाप शुद्ध होगी और ऐसी प्रवस्था हो, उसे सचिव या पीठाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

11. याचिकाओं हस्तादि का लिखित होना (1) प्रत्येक शपथ पत्र, आवेदन पत्र—या याचिका स्वच्छ एवं पठनीय रूप से पूरे आकार के कागज पर एक ही तरफ बोहरे स्थान के अन्तर पर लिखित, टंकित, साइक्लोस्टाइल की हुई या मुद्रित होगा और उस पर अलग-अलग पृष्ठ संख्या डाली जायेगी।

(2) किसी भी शपथ पत्र, आवेदन पत्र—या याचिका में व्यक्ति तारीख और संख्या, संख्याओं और शब्दों दोनों में व्यक्त किए जाएंगे और जहां उनमें लिखित तारीख, ईसवी, सम्बन्ध के अनुसार नहीं है वहां ईसवी, सम्बन्ध की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र — या याचिका अनुच्छेदों में विभाजित होंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र — या याचिका अलग-अलग अनुच्छेदों में विभाजित होंगे जो क्रमांकित किया जाएगा और उसके ऊपर विषय वस्तु कम्पनी का नाम जिसका कि वह है लिखा जाएगा।

13. सामान्य शीर्षक फार्म संख्या 1 में होगा। समस्त कार्यवाहियों में, चाहे वे मौखिक हों या अन्तर्वादी और विज्ञापनों तथा सूचनाओं का सामान्य शीर्षक फार्म संख्या 1 अनुलग्नक II में होगा।

14. याचिका दायर करने की प्रक्रिया (1) विनियम 35 और 37 की शर्तों की तहत पीठ के लिए एक याचिका अनुलग्नक II में जमाए गए फार्म संख्या 1 में तैयार की जाएगी और याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पीठ के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी या पावती समेत डाक से रजिस्ट्री द्वारा पीठाधिकारी या जैसी प्रवस्था हो सचिव के नाम भेजा जाएगा।

(2) जहां प्रतिपक्षियों की संख्या एक से अधिक हो, जहां याचिकाकर्ता द्वारा याचिका की अपनी प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी जितने कि प्रतिपक्षी हों।

बशर्त कि जहां प्रतिपक्षियों की संख्या पांच से अधिक हो, वहां सचिव या पीठाधिकारी याचिकाकर्ता को याचिका की प्रतिरिक्त प्रतियां प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने के समय दायर करने की अनुमति दे सकता है।

(3) याचिका कर्ता अधिनियम की धारा 49, 79, 80ए, 111, 113, 118, 144, 163, 188, 196, 219, 225, 284, 304, 307 तथा प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22क के अलावा अन्य सभी हवाल्लों या याचिकाओं की प्रति सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार को जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी आती है वेग और अपनी याचिका हवाल्ले के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय की पावती भी संलग्न करेगा जिसे याचिका हवाल्ला इस प्रकार दिया गया है।

परन्तु अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस शुद्धा कम्पनी धारा 17 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका की एक प्रति क्षेत्रीय निदेशक को भी देगी।

अधिनियम की धारा 235, 237, 250, 397, 398, 408 और 409 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका या शिकायत के मामले में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी दी जाएगी।

4. (क) उप विनियम (1) और (2) में कही गई बातों के बावजूद पीठ एक से अधिक लोगों को सम्मिलित रूप से याचिका दायर करने की अनुमति दे सकती है यदि कार्य कारण तथा मांगी गई राहत की मद्दे नजर रखते हुए पीठ इस बात से सन्तुष्ट है कि उनका मामले में समान रूप से अभिरुचि है।

(ख) इस प्रकार की अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जिनमें याचिकाकर्ताओं का एक ही याचिका में शामिल होना अधिनियम द्वारा विशेष रूप से स्वीकार्य है।

5. अधिनियम की धारा 53(क) (9) के अन्तर्गत दायर याचिका के अलावा अन्य प्रत्येक याचिका के साथ इसे सत्यापित करना हुआ एक शपथपत्र होगा और उसे प्रथम पृष्ठ के रूप में बनाया जाएगा और वह शपथकर्ता का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय और पूर्ण आवासीय पता व्यक्त करेगा तथा शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अधिनियम की धारा 558 में निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष उसकी शपथ ली जाएगी।

6. जहां शपथकर्ता को वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता जिसके समक्ष उपविनियम 6 के अन्तर्गत शपथ-पत्र पर शपथ लेनी है तो उसकी शिमाहत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे वह व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ लेनी है जानता हो।

7. उपविनियम 5 के अन्तर्गत प्रत्येक शपथ-पत्र स्पष्ट रूप से तथा पृथक-पृथक उक्त वक्तव्यों को इंगित करेगा जो सत्य हैं:—

(क) शपथकर्ता की जानकारी के अनुसार।

(ख) शपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ग) शपथकर्ता के विश्वास के अनुसार तथा

(घ) कानूनी सलाह के ऊपर आधारित सूचना के अनुसार।

8. जहां उप विनियम (5) में कहा गया कोई वक्तव्य शपथकर्ता के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सही कहा गया है, जहां शपथ-पत्र में उस व्यक्ति का नाम और पूरा आवासीय पता लिखा जाना चाहिए जिससे कि सूचना शपथकर्ता को मिली है और यह भी लिखा जाना चाहिए कि शपथकर्ता यह विश्वास का है कि सूचना सही है।

15. याचिका का प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण. (1) पीठ का कार्यालय प्रत्येक याचिका पर उस तारीख को बर्ज करेगा जब याचिका दायर की गई।

(2) यदि जांच के बाद याचिका ठीक पाई जाती है तो इसे पंजीकृत किया जाएगा और इस पर क्रम संख्या डाली जाएगी।

(3) यदि जांच के बाद याचिका खोखली पाई गई और पाया गया वष केवल रस्मी प्रकृति का है तो सचिव या पीठाधिकारी पक्ष की अपनी उपस्थिति में उसमें सुधार देने की अनुमति दे सकता है और यदि वह वष रस्मी तौर पर नहीं है तो सचिव या पीठाधिकारी याचिकाकर्ता को सुधार हेतु जो समय उचित समझे उसकी सहमति से दे सकता है।

(4) जहाँ याचिकाकर्ता उप-विनियम (3) के अंतर्गत दिए गए सचिव या न्यायपीठ अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति है वहाँ मामला न्यायपीठ के समक्ष आदेश के लिए रखा जाएगा और न्यायपीठ का एकल सदस्य आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगा जो न्यायपीठ के निर्देश माने जायेंगे।

16. याचिका की विषय-वस्तु—विनियम 37 के अंतर्गत दायर की गई अर्जी के अलावा प्रत्येक याचिका कंपनी का नाम इसकी हैसियत, नियमन की तारीख इसके पंजीकृत कार्यालय का पता अधिकृत पूंजी विभिन्न अंशों के विभाजन तथा बरीयता प्राप्त शेयरों की निर्गमन की शर्तों, यदि कोई हो, समेत प्रवृत्त पूंजी, संक्षेप में मुख्य उद्देश्य, जिनके लिए कंपनी बनाई गई थी, कंपनी के वर्तमान व्यापार-कार्य का उल्लेख करेगी एवं स्पष्ट रूप से इस प्रकार की याचिका के आधार का शीर्षक और प्राप्ति राहत की प्रकृति का भी उल्लेख करेगी।

17. अन्तर्बैती अर्जी की विषय-वस्तु—याचिका दायर करने के उपरान्त अन्तरिम आदेश या निवेश के लिए दायर की गई अर्जी, जहाँ तक सम्भव हो, प्राथम अनुसूचक II में होगी और विनियम 14 में बताई गई रीति से सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र से युक्त होगी।

बशर्ते कि अन्तरिम राहत या निवेश प्राप्त करने के लिए एक पृथक अर्जी देना आवश्यक न होगा सिवा याचिका दायर करने के लिए बिलम्ब की समा करने के लिए यदि मूल याचिका में, इसकी प्रार्थना की गई हो।

18. (1) याचिका अनुसूचक III निर्धारित वस्तुओं से युक्त होगी और वस्तुओं की विषय सूची भी साथ में लगी होगी।

(2) उप-विनियम (i) कहे गए वस्तुओं प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं और उन्हें क्रमानुसार चिह्नित किया जायेगा जैसे क-1, क-2, क-3 आदि आदि।

(3) जहाँ याचिका प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, हाजिरी का शपथ याचिका के साथ संलग्न किया जायेगा।

बशर्ते कि जहाँ याचिका एक वकील द्वारा दायर की जाती है वह एक बिधिवत् लिखा गया वकालतनामा साथ में होगा।

न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित होने का पक्षकार का अधिकार

19. (1) प्रत्येक पक्षकार न्यायपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(2) पक्षकार लिखित रूप से, एक वकील, जाटेंड एकाउण्टेंट या कास्ट और बन्स एकाउण्टेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी या पूर्णकालिक तौर पर व्यवसाय में संलग्न सेक्रेटरी को अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। एक कंपनी बिधिवत् प्राधिकृत करके न्यायपीठ के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए अपने किसी निदेशक को नियुक्त कर सकती है।

20. बहुल उपाय एक याचिका एकल कार्यकरण पर आधारित होगी और एक या एक से अधिक राहतों के लिए प्रार्थना कर सकती है बशर्ते कि वे एक दूसरे से परिणाम स्वरूप जुड़े हों।

ब 21. सूचना की तामील और न्यायपीठ द्वारा जारी प्रक्रिया : (1 न्यायपीठ) द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना या प्रक्रिया न्यायपीठ द्वारा निर्देशित नीचे निम्ने किसी भी तरीके से तामिल की जा सकती है :-

- (1) स्वयं पक्षकार द्वारा तामील
- (2) न्यायपीठ के कार्यालय एक संदेशवाहक द्वारा वक्ता तामील
- (3) पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत डाक द्वारा।
- (4) पावती शुभा रजिस्ट्री डाक द्वारा यदि न्यायपीठ द्वारा ऐसा आदेश दिया गया हो।
- (5) जहाँ केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार, वहाँ संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा या विधि मंत्रालय की सचिवालय शाखा द्वारा या केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता द्वारा।
- (6) जहाँ राज्य सरकार एक पक्षकार हो वहाँ मुख्य सचिव या राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा।

(2) जहाँ एक कंपनी को नोटिस तामील करना अपेक्षित हो वहाँ इसे धारा 51 में बताए गए तरीकों से तामील किया जायेगा या विदेशी कंपनी के मामलों से इसे धारा 596 में बताए तरीकों से तामील करना होगा और इसे किसी ऐसे अन्य तरीके से भी तामील किया जा सकता है जिसका निर्देश सचिव या न्यायपीठ अधिकारी करें।

(3) उप विनियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को तामील की जाने वाली नोटिस या अन्य दस्तावेज इस प्रकार के व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को देकर तामील किये जायेंगे, जहाँ वह प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होता है या फिर इसे पावती युक्त रजिस्टर्ड चिट्ठी से उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जायेगा।

(4) जहाँ रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तामील की गई हो तो सचिव या न्यायपीठ अधिकारी यदि पावती प्राप्त न हुई हो, नोटिस के तामील होने की पर्याप्तता का प्रश्न निर्णीत करेंगे।

(5) जहाँ रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई नोटिस "इनकार किया" की टिप्पणी के साथ पोस्ट आफिस द्वारा वापस की गई हो तो नोटिस को बिधिवत् तामील शुभा माना जायेगा।

(6) याचिका या ह्वाजे के बारे में न्यायपीठ द्वारा जारी की गई प्रत्येक नोटिस, यदि उसका अर्थवा आदेश न हो, याचिका या ह्वाजे जैसी भी बात हो, की प्रति से युक्त होगी।

(7) उपविनियम (1) से (6) में लिखित किसी बात के बावजूद जहाँ, किसी भी कारणवश, समस्त प्रतिपक्षियों का नोटिस तामील करना व्यावहारिक नहीं है, जैसा कि प्रत्येक मामले में न्यायपीठ निर्देश दे, नोटिस को अंगघारियों वित्ताचारों या उनके किसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा तामील किया जा सकता है।

(8) ऐसे मामलों में, न्यायपीठ यह तय करेगी कि सार्वजनिक विज्ञापन का व्यय कौन वहन करेगा।

22. (1) याचिका के विरोध का इरादा रखने वाला प्रत्येक प्रतिपक्षी याचिका के उत्तर तथा जिन वस्तुओं पर वह निर्भर करना चाहता है उनकी तीन प्रतियां न्यायपीठ के कार्यालय में ऐसी अवधि के भीतर दायर करेगा जिसे न्यायपीठ तय करें। पर यह अवधि नोटिस तामिल होने की तारीख से 15 दिन से ज्यादा की न होगी।

(2) उपविनियम (1) के अंतर्गत दायर किये गये उत्तर में प्रतिपक्षी विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में कहे गए तथ्यों को स्वीकार, इनकार या स्पष्ट करेगा और इस प्रकार के अनिश्चित तथ्यों का भी उल्लेख कर सकता है जो मामले में उचित ध्याप के लिए आवश्यक पाये जाय। इस प्रकार दायर किया गया उत्तर विनियम 14 में प्राविधित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा।

(3) उप-विनियम (1) में संदर्भित दस्तावेज भी उत्तर के साथ वापस किए जाएंगे और उन पर अनुसूचनाक र-1, र-2, र-3 आदि प्राविधिकृत किया जायेगा।

(4) प्रतिपक्षी उपविनियम (1) में संदर्भित दस्तावेजों की विधिवत सत्यापित सत्य प्रतिरूपि समेत उत्तर की प्रति की याचिका कर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई हो, को तामील करेगा और न्यायपीठ के कार्यालय में इस प्रकार की तामील का साक्ष्य वापस करेगा।

(5) न्यायपीठ, यदि संतुष्ट हो तो उत्तर को निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वापस करने को अनुमति पर्याप्त कारण दर्शाने पर दे सकती है।

23. याचिकाकर्ता द्वारा प्रति-उत्तर वापस करना :—जहाँ प्रतिपक्षी ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख करता है जो विनियम 22 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत मामले के उचित निर्णय के लिए जरूरी हो, वहाँ न्यायपीठ याचिका कर्ता को प्रतिपक्षी द्वारा वापस किए गए उत्तर का प्रति-उत्तर देने की अनुमति दे सकती है। धारा 22 में उल्लिखित प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन के साथ इस प्रकार के उत्तर को वापस करने के बारे में लागू होगी।

24. अतिरिक्त सूचना/साक्ष्य मंगाने के लिए न्यायपीठ की शक्ति :—न्यायपीठ याचिका पर आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों या उनमें से एक या एक से अधिक को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य जिन्हें न्यायपीठ निम्न अभिप्रेतों के लिए आवश्यक समझे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है :

(क) याचिका में लगाए गए आरोपों के प्रति अपने को संतुष्ट करने के अभिप्रेत से, या

(ख) किसी सूचना को सुनिश्चित करने के लिए जो न्यायपीठ के विचार में याचिका पर आदेश पारित करने के लिए इसे सक्षम बनाने के वास्ते आवश्यक है।

25. याचिका की सुनवाई :—न्यायपीठ यदि कार्यवाही किसी भी अवस्था में पर्याप्त कारण दर्शाया जाये, तो पक्षकारों या उनमें से किसी एक को समय दे सकती है और याचिका या अर्जी पर सुनवाई रोक सकती है। न्यायपीठ इस प्रकार के रोक के कारण उत्पन्न खर्च के बारे में जो भी उचित समय वह आदेश पारित कर सकती है। जहाँ कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता वहाँ अपनाये जाने वाली प्रक्रिया।

26. (1) जहाँ याचिका या किसी आवेदन पत्र पर सुनवाई के लिए निश्चित तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर जमके लिए सुनवाई रोक दी गई है, याचिकाकर्ता या आवेदक, जो भी हो, याचिका या आवेदन पत्र पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है, न्यायपीठ अपने विवेकानुसार याचिका या आवेदन पत्र को या तो बूक के कारण निरस्त कर सकती है या उसे सुनकर उस पर एक तरफा फैसला दे सकती है।

(2) जहाँ एक याचिका या आवेदन पत्र बूक के कारण निरस्त कर दिया गया हो और याचिका कर्ता या आवेदक निरस्तीकरण के तीस दिन के भीतर अर्जी देता है और न्यायपीठ को इस बात से संतुष्ट करता है कि जब याचिका या आवेदन पत्र सुनवाई के लिए सौंपा गया था तो उसके पास अनुपस्थित होने का पर्याप्त कारण था, तो न्यायपीठ याचिका या आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए आदेश को रद्द कर सकती है और उसे पुनः स्थापित कर सकती है :

बशर्ते कि जहाँ मामले को गुण-बोध के आधार पर निपटाया गया है वहाँ फैसले को बदला नहीं जायेगा।

(3) जहाँ, सुनवाई के लिए निश्चित तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर जिसके लिए सुनवाई रोक दी गई हो याचिका कर्ता याचिका पर सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होता है, वहाँ न्यायपीठ अपने विवेकानुसार सुनवाई रोक सकती है या याचिका पर एक-तरफा सुनवाई करके फैसला दे सकती है।

(4) जहाँ प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षियों के विरुद्ध याचिका पर एकतरफा सुनवाई हुई है इस प्रकार के प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षीगण तीस दिन के भीतर न्यायपीठ को इसे रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और यदि प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षीगण न्यायपीठ को इस बात से संतुष्ट करते हैं कि उस पर या उन पर कोई भी विधिवत तामील नहीं हुई थी या वह दावे याचिका पर सुनवाई के समय पर्याप्त कारणोंबम उपस्थित होने से बबरुद्ध हो गए थे तो न्यायपीठ उसके या उनके विरुद्ध पारित एक तरफा आदेश को ऐसी शर्तों पर जिसे वह उचित समझे निरस्त कर सकती है और याचिका पर सुनवाई की तारीख तय करेगी :

बशर्ते कि जहाँ एक तरफा आदेश ऐसा है कि यह केवल एक प्रतिपक्षी के विरुद्ध हो निरस्त नहीं किया जा सकता, तो इसे समस्त प्रतिपक्षियों या किसी प्रतिपक्षी के खिलाफ निरस्त किया जा सकता है :

बशर्ते कि विनियम 21 के उप-विनियम (7) के अंतर्गत आने वाले मामलों में न्यायपीठ केवल इस आधार पर आदेश को निरस्त नहीं करेगा कि एक अंशद्वारा या लेनदार को याचिका को सूचना नहीं मिली थी।

27. पुनर्विलोकन :—(1) कोई भी पक्षकार जो यह मानता हो कि वह न्यायपीठ द्वारा अभिलेख देखते ही प्रकट होने वाली भूलों या गलतियों के कारण किये गये आदेश से बुखित है और अपने विरुद्ध किए गए आदेश का पुनर्विलोकन चाहता हो वह उस न्यायपीठ से उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें आदेश पारित किया है।

(2) पुनर्विलोकन के लिये कोई भी आवेदन पत्र आदेश की तारीख से 30 दिन के बाद नहीं प्रस्तुत किया जायेगा और न ही ऐसी किसी अर्जी पर विचार किया जायेगा यदि इसके साथ विनियम 14 के अन्तर्गत बताई विधि के अनुसार आवेदन पत्र को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र युक्त न हो।

(3) जहाँ न्यायपीठ को यह लगे कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह आवेदन पत्र को निरस्त कर देगी परन्तु जहाँ न्यायपीठ इस विचार को है कि पुनर्विलोकन के लिए की गई अर्जी मंजूर कर देनी चाहिए वहाँ यह उसे मंजूर कर देगी :

बशर्ते कि ऐसी कोई भी अर्जी विरोधी पक्षकार को उन आदेश के समर्थन में जिसके पुनर्विलोकन के लिए अर्जी दी गई है समर्थ बनाने के लिए अवसर विय बिना मंजूर नहीं की जायेगी।

28. कानूनी प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन :—(1) न्यायपीठ के समक्ष कार्यवाही के चलते रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की अवस्था में मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि इस प्रकार की मृत्यु के तीस दिन के भीतर रेकार्ड पर आवश्यक पत्रकार की हैसियत से लाये जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) में निर्धारित समय के अन्दर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता वहाँ मृत्यु पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो जायेगी :

बशर्ते कि सुन्दर और पर्याप्त कारणोंबम, न्यायपीठ, आवेदन पत्र देने पर समाप्ति का आदेश का निरस्तीकरण और कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन कर सकती है।

29. न्यायपीठ के आदेश :—(1) न्यायपीठ का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और वह उस न्यायपीठ के सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो आदेश पारित करती है।

(2) न्यायपीठ का कोई भी आदेश जो किसी पक्षिका अधिष्ठान रिपोर्ट या प्रेम में प्रकाशन योग्य पाया जाता है इस प्रकार के प्रकाशन के लिए उन शर्तों पर विमोक्षित किया जा सकता है जिन्हें कोई समान या विशेष आदेश निर्धारित करें।

(3) प्रत्येक अन्तरिम शाहत को संज्ञा, प्रस्वीकरण या संशोधित करने हुये प्रत्येक अन्तरिम आदेश पर किसी याचिका या हवाले पर पत्र किये हुए अन्तिम आदेश को याचिका या आवेदनकर्ता प्रतिनिधियों या अन्य सम्बन्धित पक्षकारों को भेजा जायेगा :

बशर्ते कि धारा 17 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन को पुष्ट करते हुए आदेश के मामलों में आदेश की दो प्रति याचिका देने वाली कम्पनी को निशुल्क दी जायेगी।

(4) यदि याचिकाकर्ता या आवेदक या किसी कार्यवाही का प्रति पक्षकारी को किसी दस्तावेज या कार्यवाही की प्रति की आवश्यकता हो तो उसे वह ऐसी शर्तों और ऐसी फीस देने पर दी जा सकती है जिन्हें न्यायापीठ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(5) न्यायापीठ ऐसे आदेश कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है जो इसके आदेश को प्रभावित बनाने के लिए या इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हों।

(6) न्यायापीठ के लिए अपने समक्ष आये किसी पक्षकार के ऊपर खर्च तय करना और इसे देने को कहना कानून लागू होगा जहाँ न्यायापीठ इस विचार की हो कि इस प्रकार का खर्च देने को कहना आवश्यक है।

30. अभिलेखों, पत्र निरीक्षण एवं प्रमाणपत्र प्रतियों की आपूर्ति :—

(1) लिखित रूप से आवेदन पत्र देने तथा प्रतिदिन 10 घण्टे की दर से मुल्क देने पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रत्येक विचाराधीन कार्यवाही या निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(2) विनियम 29 के उपविनियम (4) के प्रावधानों की शर्त पर एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, अन्तिम आदेश पास हो जाने पर न्यायापीठ की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त कारण बताने पर याचिका, उत्तरों और प्रत्युत्तरों की प्रतियाँ ऐसे मुल्क को जिसे न्यायापीठ द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय किया जाए, देने पर प्राप्त कर सकता है।

(3) एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है न्यायापीठ द्वारा अन्तिम आदेश पास करने के उपरान्त अधिकार स्वरूप आदेशों की प्रतियाँ ऐसे मुल्क को, जिसे न्यायापीठ ने किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय किया हो, देकर प्राप्त कर सकता है।

(4) सिवा उस व्यक्ति को सहमति के साथ जिनके द्वारा वह प्रस्तुत की गई थी या न्यायापीठ के आदेश के अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्ति को जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है कार्यवाही के अभिलेखों के निरीक्षण करने का या साक्ष्य में प्रस्तुत प्रतियों की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार न होगा।

31. सचिव की शक्तियाँ और कार्य

(1) सचिव बोर्ड का मुख्य अधिकारी होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पादन करेगा।

(2) बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य के सम्पादन में, सचिव से ऐसी सहायता ले सकता है जो वह उचित समझे और सचिव बोर्ड को सहायता देने के लिए बाध्य होगा।

(3) विशेष रूप से एवं इन नियमों के सामान्य अर्थ पर बिना प्रतिकूल प्रभाव वाले सचिव की निम्न शक्तियाँ होंगी, और वह निम्न कर्तव्यों का सम्पादन करेगा, नामधः—

(क) सचिव के पास प्रधान न्यायापीठ के अभिलेख रहेंगे;

(ख) सचिव प्रधान न्यायापीठ से सम्बन्धित सभी याचिकाएँ आवेदन पत्र या हवाले प्राप्त करेंगे।

(ग) सचिव प्रधान न्यायापीठ को प्रधान न्यायापीठ द्वारा प्रयोग किये जाने वाली शक्तियों की कार्यवाही में सहायता करेगा।

(घ) सचिव के पास सूचना अभिलेख संग्रहण और न्यायापीठों के अभिलेखों का निरीक्षण करने या कराने की शक्ति होगी।

(ङ) सचिव प्रधान न्यायापीठ द्वारा पारित आदेशों की अधिभुक्त करेगा।

(च) सचिव प्रधान न्यायापीठ तथा अन्य न्यायापीठों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(छ) बोर्ड की सरकारी सील सचिव की रक्षा और नियंत्रण में रहेगी।

(ज) सचिव को केन्द्रीय सरकार या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों और फर्मों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी सूचनाओं को एकत्र करने का जो अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यों के क्षमतापूर्वक सम्पादन के लिये लाभप्रद समझी जाये और उन सूचनाओं को बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

32. न्यायापीठ अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्यः—इन विनियमों के अन्तर्गत अन्यत्र प्रवृत्त शक्तियों के अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायापीठ के किसी सामान्य या विशेष आदेश की शर्तों के तहत न्यायापीठ अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, नामधः

(i) समस्त याचिका और आवेदन पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करना जिनमें हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शामिल होंगे;

(ii) पंजीकृत होने के पूर्व याचिकाओं और आवेदन पत्रों की जाँच से उत्पन्न समस्त प्रश्नों का फैसला करना;

(iii) न्यायापीठ के समक्ष प्रस्तुत किसी भी याचिका या आवेदन पत्र के अधिनियम तथा विनियम के अनुसार संशोधन कराना;

(iv) न्यायापीठ के निवेदों की शर्तों पर याचिकाओं या आवेदन पत्रों या अन्य कार्यवाहियों पर पहली सुनवाई तय करना और उसकी सूचना जारी करना;

(v) अभिलेख के किसी रस्सी संशोधन का निदेश देना;

(vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियाँ देने का आदेश देना;

(vii) न्यायापीठ के अभिलेखों के निरीक्षण का आदेश देना;

(viii) नोटिसों की तामील या अन्य प्रक्रियाओं को शुरू करने, नई नोटिसें जारी करने की प्रक्रियाओं और इस प्रकार की प्रक्रियाओं को वापस करने की तारीख बढ़ाने और उत्तर या प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को वापस करने के लिये पन्द्रह दिन से अधिक समय न देने और उक्त समय के भीतर जाने पर न्यायापीठ के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने सम्बन्धी समस्त मामलों को निपटाना;

(ix) याचिका या आवेदन पत्र के विचाराधीन होने के दौरान मृत्यु की तारीख से तीन दिनों के भीतर मृत पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिये आवेदन पत्र स्वीकार करना,

(x) प्रतिस्थापन के आवेदन पत्र को स्वीकार करना और निपटाना, सिवाय उम्र स्थिति में जबकि प्रतिस्थापन में समाप्ति के आदेश का निरस्त होना निहित होगा;

(xi) पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को वापस करने के बारे में आवेदन पत्रों को स्वीकार करना और निपटाना।

2. न्यायापीठ अधिकारी के कर्तव्य (ii), (iii), (iv) और (vii) के अन्तर्गत किसी फीमले की अपील बुद्धित पक्षकार द्वारा सचिव को इस प्रकार के आदेश के प्रेषित होने के पन्द्रह दिन के भीतर करनी होगी और उस पर सचिव का फैसला अंतिम होगा।

33. याचिकाओं एवं आवेदन पत्रों का रजिस्टरः—(1) न्यायापीठ के कार्यालय में दो अलग-अलग रजिस्टर रखे जायेंगे—एक न्यायापीठ के समक्ष दायर की गई याचिकाओं के लिये और दूसरा आवेदन पत्रों के लिये।

(2) प्रत्येक रजिस्टर में, जिसका उल्लेख उपविनियम (1) में किया गया है निम्नलिखित विवरण भरे जायेंगे, नाम—

- (क) याचिका या आवेदन पत्र के क्रम संख्या और इसके प्रतिनिधित्व, आवेदन पत्र के मामले में उस याचिका की क्रम संख्या जिससे यह संबंधित है।
- (ख) याचिका या आवेदन पत्र की प्रस्तुति या पावसी की तारीख।
- (ग) उस कम्पनी का नाम जिससे यह संबंधित है।
- (घ) याचिका कर्ता या आवेदन कर्ता का नाम और पता।
- (ङ) याचिका या आवेदन पत्र के अन्य पक्षकारों का नाम और पता और पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों प्रादि कोई हो, का नाम और पता।
- (च) कानून का वह प्रावधान जिसके अन्तर्गत याचिका या आवेदन पत्र दायर किया गया है।
- (छ) मांगी गई राहत की प्रकृति।
- (ज) याचिका या आवेदन पत्र के निपटारे जाने की तारीख।
- (झ) न्यायापीठ द्वारा किये गये आदेश की प्रकृति।
- (ञ) वह तारीख जब रस्मी आदेश निर्मित किया गया और पक्षकारों को प्रेषित किया गया।
- (ट) पुनर्विलोकन, यदि कोई हो।

(3) प्रति वर्ष के लिये पृथक रजिस्टर खोले जायेंगे और याचिकाओं की प्रत्येक रजिस्टर स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा जायेगा और आवेदन पत्रों का रजिस्टर आठ वर्ष के लिये सुरक्षित रहेगा।

34. फीस—(1) अनुसूचक III में उल्लिखित अनेक मामलों के बारे में प्रत्येक याचिका की एक निर्धारित फीस दी जायेगी;

बशर्त कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, या केन्द्रीय सरकार की तरफ से किसी अन्य अधिकारी द्वारा दायर याचिका हवाले पर कोई फीस देय या बसूल पाने योग्य न होगी।

बशर्त कि किसी ऐसे मामले में जिसमें कार्यवाही बोंड स्वयं प्रारम्भ करता हो कोई फीस देय या बसूल पाने योग्य न होगी।

(2) निर्धारित फीस प्रति अन्तर्द्वितीय आवेदन पत्र पर एक सी रुपये प्रति आवेदन पत्र की दर से लगाई और बसूल की जायेगी।

बशर्त कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक या केन्द्रीय सरकार की तरफ से किसी अन्य अधिकारी द्वारा दायर याचिका या हवाले पर कोई भी फीस देय या बसूल पाने योग्य न होगी।

(3) प्रधान न्यायापीठ या उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की न्यायापीठों के समक्ष दायर याचिका या आवेदन पत्र के बारे में इन विनियमों के अन्तर्गत देय फीस एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा की जायेगी जो बेंगलूर और लेखा अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग, जैसी स्थिति हो, नई दिल्ली/कलकत्ता/मद्रास/बम्बई के नाम से बनवाया जायेगा।

अध्याय III

कार्य विभागों के मध्य में विवेक उपबन्ध

35. कम्पनी विधि बोर्ड की हवाला—कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा बोर्ड को प्रेषित अधिनियम की धारा 621 के अन्तर्गत कोई हवाला या बोर्ड को अधिनियम की धारा 250, 269, 388-ख और 408 के अन्तर्गत प्रेषित कोई हवाला या एक कम्पनी द्वारा प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (4) के अन्तर्गत कोई हवाला प्रारूप संख्या 3 में एक आवेदन पत्र के रूप में होगा और अनुसूचक III में उल्लेख किये गये दस्तावेजों से युक्त होगा।

36. धारा 17 के अन्तर्गत याचिका—(1) कम्पनी, धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई याचिका दायित्व करने के एक माग से अन्यून पूर्व;

(i) साधारण सूचना कम से कम एक बार उस जिले की, जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, प्रधान भाषा में, उस जिले में प्रचलित अक्षरों में और कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित और उस जिले में प्रचलित अक्षरों में अंग्रेजी में प्रकाशित करेगी। साधारण सूचना में प्रकाशित करेगी। साधारण सूचना में अर्थों का सार स्पष्ट किया जायेगा और यह कथित किया जायेगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका आपन के प्रस्थापित परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भाव्य है सूचना के प्रकाशन की तारीख के एकतीस दिन के भीतर न्यायापीठ के अधिकारी को अपने हित की प्रकृति और याचिका के अवरोधक करने के आधाओं की सूचित कर सकत, है।

(ii) यदि धारा 17 द्वारा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजने की प्रतीक्षा न हो कम्पनी के प्रत्येक निदेशक धारक और लेनदार पर उपर के वाक्य (i) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सूचना की व्यक्तिगत रूप से पोस्टल-प्रमाण पत्र द्वारा तामिल करेगी।

(iii) जहाँ याचिका में याचिकाकर्ता कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाने की इच्छा की गई हो वहाँ याचिका की प्रति के साथ सूचना उस राज्य सरकार के मुख्य सचिव पर, जिस राज्य में याचिकाकर्ता कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, या जहाँ कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, वहाँ उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक पर भी तामिल की जायेगी।

(2) याचिका का विरोध करने वा आशय रखने वाला हर व्यक्ति यथास्थिति, सूचना की तारीख या प्रकाशन की तारीख से एकतीस दिन के भीतर शपथ पत्र द्वारा समायित आक्षेपों की मूल रूप में न्यायापीठ अधिकारी को परिचित करेगा या पटित करवायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा और आक्षेपों की एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर तामिल करेगा।

(3) यदि उप-विनियम (3) के किसी उपबन्ध के अनुपालन में कोई व्यक्तिगत किया जाता है तो सम्पूक्त व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने याचिका में प्रभावित परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है।

परन्तु न्यायापीठ यदि वह ठीक समझे पूर्वोक्त समय की समाप्ति के पश्चात भी और अन्तिम मुनबाई के पूर्व, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को याचिका कर्ता कम्पनी को सूचना देने के पश्चात आक्षेप दायित्व करने की अनुशा दे सकत है।

(4) याचिकाकर्ता कम्पनी सूचनाओं के भेजे जाने, प्रकाशन और तामिल को एक शपथ पत्र द्वारा साबित करेगी और ऐसा शपथ पत्र अर्थों के साथ लगाया जायेगा।

(5) धारा 17 में दायर की गई याचिका के अनिवार्य रूप से कम्पनी के नवागों की याचिका दायर करने के पूर्व यथासम्भव निकटतम तारीख तक अद्यतन सूची को किसी भी हालत में उप-विनियम (8) में कही गई तारीख से दो महीने अधिक पहले की न होगी, तथा प्रत्येक को देय रकम के सम्बन्ध में सूचना होगी। याचिका के साथ लेनदारों और क्रेडिटर्स धारकों की एक सूची भी संलग्न होगी।

(6) याचिकाकर्ता कम्पनी का सचिव, यदि हो, और कम्पनी के दो निदेशकों से अन्यून जिनमें से एक उसका प्रबन्ध निदेशक, यदि कोई हो, होगा उप-विनियम (8) की सूची के बारे में इस आशय के शपथ पत्र द्वारा सत्यापित करेंगे कि उन्होंने कम्पनी के मामलों में पूर्ण जांच कर ली है और ऐसा करने के पश्चात उनकी यह राय है इस प्रकार सत्यापित सूची सही है, ऐसे ऋण या दावों की सूची में जो आक्रामकता की वशा में संदाय है या सुनिश्चित नहीं है, दिए गए प्राक्कलित मूल्य तथा: ऐसे ऋणों और

धाराओं की पुष्टि कम्पनी की धर्मियों और अभिलेखों से होती है और उसमें जानकारी में कम्पनी के कोई और कण या उसके विरुद्ध और कोई दावे नहीं हैं।

(7) लेनदारों और डिबेन्चर धारकों की उनके नाम, पते और प्रत्येक को देय शक्ति दर्शानी हुई विधिवत अधिप्रमाणित सूची भी प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी रहेगी और उनके निरीक्षण की वादा रखने वाला कोई व्यक्ति कारोबार के सामान्य समय के दौरान कम्पनी को इस रुपये संदाय करके उनका निरीक्षण कर सकता है तथा उद्धरण ले सकता है।

(8) जहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय निदेशक का जैसा भी हो, याचिका और उसके विरोध में की गई याचिका और प्रतिवेदन पर शपथपत्र मुनवाई के लिए तैयार हो, न्यायपीठ उसे उस निमित्त तयशुदा तारीख पर सुनेगी जिसकी सूचना रजिस्ट्रार पत्र करणों को विधिवत देगा।

(9) याचिका की मुनवाई पर न्यायपीठ या तो याचिका को अन्तिम रूप में निपटा देगी या ऐसे निदेश दे सकती है जो आवश्यक होंगे जिनमें पूरक शपथ पत्र का दायर करना या प्रथिमा सम्बन्धी रस्मों का अनुपालन शर्तक होगा या मामने को रोक सकती है।

37. अधिनियम की धारा 58(8) के अन्तर्गत आवेदन पत्र :—अमाकर्त द्वारा धारा 58 की उपधारा (9) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक आवेदन पत्र फर्म संख्या I अनुलोकक II में दो प्रतियों समेत दायर की जायेगी।

38. धारा 397 एवं 398 के अन्तर्गत दायर याचिका :—धारा 397 या 398 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका बिना कोई भी प्रत्युक्ति के वापस नहीं की जायेगी और जहाँ याचिका धारा 399 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सदस्य या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है वापस लेने की याचना के सम्बन्ध में नोटिस केन्द्रीय सरकार को देनी होगी।

39. धारा 407 के अन्तर्गत याचिका :—धारा 407 की उप धारा (1) के वाक्य (ख) के अन्तर्गत उसमें बताये गये किसी भी व्यक्ति को कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक या अन्य निदेशक या मैनेजर नियुक्त होने का अनुमति प्राप्त करने की याचिका यह उल्लेख करेगी कि क्या इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के आशय की नोटिस केन्द्रीय सरकार को दी गई है और इस प्रकार की नोटिस को एक प्रति याचिका के साथ संलग्न होगी।

40. धारा 621 के अन्तर्गत हवाले :—(1) एक अपराध को क्षमा करने के बारे में प्रत्येक आवरण पत्र एक कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार को स्पष्ट रूप से अपराध की प्रकृति, तारीख और समय जिनके दौरान अपराध किया गया था जारी रखा गया, कम्पनी के अधिकारियों के नाम व पते जिन्होंने अपराध किए हैं और की गई प्रार्थना बताते हुए दिया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार आवेदन पत्र को, अपने अधिभक्त समेत, कोई या क्षेत्रीय निदेशक को, जैसा भी हो आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर भेज देगा।

(3) प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक कोई के सामान्य या विशेष आदेश के तहत एक अपराध को क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा।

41. इन विनियमों के प्रावधान जहाँ तक हो सके, एकाधिकार अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत दायर की गई याचिकाओं पर भी लागू होंगे।

42. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत हवाले :—कोई को कोई हवाला करने के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रावधान अपवादश्रयक 22 की उपधारा (4) के वाक्य (ग) के अन्तर्गत जो हवाल किए जायेगे उन पर लागू होंगे।

अध्याय IV

43. समय में वृद्धि :—जहाँ किसी कृत्य को करने या किसी दस्तावेज या प्रतिवेदन को दायर करने के लिए इन विनियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत कोई अवधि तय की गई है या न्यायपीठ द्वारा स्वीकृत की गई है, न्यायपीठ, अपने विवेकानुसार समय-समय पर इस प्रकार की अवधि को बढ़ा सकती है भले ही इन विनियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत तय की गई अवधि या न्यायपीठ द्वारा स्वीकृत अवधि समाप्त हो गई हो।

44. न्यायपीठ की अस्तनिहित शक्ति की व्याप्ति :—इन नियमों में किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि वह न्यायपीठ की उन अस्तनिहित शक्तियों को सीमित शब्दा प्रमाणित करती है जो न्याय के उद्देश्य से या न्यायपीठ की आदेशिका को रोकने के लिए आवश्यक हों।

45. आदेशों के संशोधन :—न्यायपीठ द्वारा किए गए आदेशों में की गई त्रुटि या गणना सम्बन्धी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या किसी त्रुटि से उनमें हुई त्रुटियों को किसी भी समय न्यायपीठ द्वारा या तत्त्वपूर्णता से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध किया जा सकेगा।

46. संशोधन करने की साधारण शक्ति :—न्यायपीठ किसी भी समय और जहाँ के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह ठीक समझे अपने समक्ष को किसी कार्यवाही में किसी मुटिया गल्ली में संशोधन कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन ऐसी कार्यवाहियों पर उठाये गये या उन पर आधारित पारस्परिक प्रश्न या विवाद को अवधारण करने के लिए किए जायेंगे।

47. न्यायपीठ को कनिष्ठ प्रयोजनों के लिए न्यायालय मानना :—न्यायपीठ को, किसी ऐसे व्यक्ति को असमयोजित करने या रद्द देने के प्रयोजन के लिए जो ऐसे न्यायपीठ के किसी निदेश या आदेश को जानबूझ कर उल्लंघन करता है, न्यायालय माना जायगा।

48. विनियमों की आवश्यकताओं का परिहार करने की शक्ति उन :—शर्तों के तहत जिनका उल्लेख किया जाये, प्रत्येक न्यायपीठ को, लिखित रूप से अभिलिखित कारणों वस, इन विनियमों की आवश्यकताओं के परिहार करने की शक्ति होगी।

49. पुस्तिका का निर्माण :—न्यायपीठ कार्यालय, यदि उचित समझ तो अधिवचन पुरा कर लेने पर पक्षकारों से पुस्तिका बनाने को कह सकता है।

[मिसिल संख्या 1/10/88-सी. एल.-5]

कम्पनी विधि बोर्ड की आज्ञा द्वारा
ए. एम. चक्रवर्ती, सचिव (कम्पनी विधि बोर्ड)

अनुसूचक--I

प्रत्येक क्षेत्र के प्रस्तुत होने वाले राज्य/संघ क्षेत्र

[देखिए विनियम 7(1)]

क्रम संख्या	क्षेत्र	राज्य/संघ क्षेत्र
1.	पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागाँव, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, का राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं मिजोरम के संघ क्षेत्र।
2.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, के राज्य और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र।
3.	दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, के राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप के द्वीप समूह।
4.	पश्चिमी क्षेत्र	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा चंडीगढ़ और नगर हवेली के संघ क्षेत्र

अनुसूचक--II

फार्म सं. -- 1

[देखिये विनियम 13 और 14]

कम्पनी का बोर्ड न्यायपीठ प्रधान न्यायपीठ/
 क्षेत्रीय न्यायपीठ, बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/दिल्ली, कम्पनी अधिनियम,
 1956 के विषय में, धारा

या
 (जहां लागू हो)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969, धारा 2क

या
 (जहां लागू हो)

प्रतिभूति करार (नियमन) अधिनियम, 1956 धारा 22क

एवं
 के विषय में याचिकाओं
 (याचिकाकर्ता का नाम एवं पता लिखिए)

या
 (जहां लागू हो)

..... याचिकाकर्ता

बनाम

..... प्रतिवर्ती

याचिका का विवरण

1. कम्पनी का विवरण याचिकाकर्ता हो या नहीं (देखिए विनियम 10)
2. याचिकाकर्ता के विवरण (लिखने की आवश्यकता नहीं है (जहाँ याचिकाकर्ता कम्पनी हो)
(नाम, विवरण, पिता, पति का नाम, व्यवसाय, श्रमा, अर्थात् अंशधारी या जमाकर्ता और याचिकाकर्ता का पता)
3. प्रतिवादी का विवरण (लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि प्रतिवादी कम्पनी हो) (नाम, विवरण, पिता/पति का नाम, व्यवसाय है सहित अर्थात् अंशधारी या जमाकर्ता और प्रतिवादी का पता)
4. न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र आवश्यक घोषित करता है कि याचिका की विषय वस्तु-न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में के भीतर है।

5. परिसीमन

याचिकाकर्ता आगे घोषित करता है कि याचिका कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा में निर्धारित परिसीमा के भीतर (जहाँ लागू हो)।

6. मामले के तथ्य

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं—

तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण तारीखवार विजिए, प्रत्येक अनुच्छेद में, जहाँ तक सम्भव हो, एक पृथक मूद्रा तथ्य या अन्यथा लिखा हो।

7. मामले को पहले दायर नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय में यह विचाराधीन है। याचिकाकर्ता आगे घोषणा करता है कि उसके पहले कोई आবেदन पत्र, याचिका या मुकदमा उस मामले में जिसके बारे में याचिका दायर की गई है, किसी न्यायालय, या किसी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड की किसी अन्य न्यायाधीश दायर नहीं की गई है और न ही ऐसा कोई अर्जी याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के समक्ष विचाराधीन है।

यदि याचिकाकर्ता ने पहले कोई आবেदन पत्र, याचिका या मुकदमा दायर किया है तो जिस पर यह विचाराधीन हो और यदि फैसला हो गया हो जो फैसले का सारांश दिया जाए।

मांगी गई राहत

8. अनुच्छेद में कहे गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करता है—
(मांगी गई राहतों को राहतों के आधार और कानून, प्रावधान, यदि कोई हो, जिनपर विश्वास किया गया है बनाते हुए निदिष्ट कीजिए)
9. अन्तरिम आदेश, यदि कोई हो, जिसकी प्रार्थना की गई हो याचिका पर अन्तिम आदेश विचाराधीन होने पर याचिकाकर्ता निम्नलिखित अन्तरिम आदेशों को जारी करने का अनुरोध करता है :—
(यहाँ पर अन्तरिम आदेशों की प्रकृति कारणों समेत बनाइये)
10. की गई याचिका या आवेदन पत्र के लिए की गई फीस साक्षी रूप में बैंक ड्राफ्ट का विवरण —

- (i) पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जिसके लिए उसे लिया गया है—
(बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, बेवोन रोड/कलकत्ता/माउण्ट रोड, मद्रास/फिरोजगढ़ मैहता रोड मद्रास)
- (ii) पंजाब नेशनल बैंक को जारी करने वाली शाखा का नाम।
- (iii) बिमांड ड्राफ्ट संख्या

तारीख

राशि

11. अनुलग्नकों की सूची

(देखिए विनियम 10 और अनुलग्नक III)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

फार्म सं.-2

(देखिए विनियम 17)

प्रावेदन पत्र की प्रकीर्ण प्रावेदन पत्र संख्या
के मूल्य याधिका सं में

ककक प्रावेदक
(प्रावेदक/प्रतिवादी)

बनाम

खखख प्रतिवादी
(प्रतिवादी/प्रावेदक)

प्रावेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य

राहत या प्रार्थना

प्रावेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

फार्म संख्या -3

(देखिये विनियम-35)

कम्पनी विधि बोर्ड समस्त प्रधान न्यायपीठ/क्षेत्रीय न्यायपीठ बम्बई/कलकत्ता/मद्रास/नई दिल्ली ।

..... का हवाला, प्रावेदन पत्र सं
कम्पनी अधिनियम, 1956/ प्रतिभूति अधिनियम, 1956 के विषय में

एवं

उक्त अधिनियम की धारा के सम्बन्ध में

(कम्पनी का नाम व पता) के विषय में

..... प्रावेदक

उन व्यक्तियों का नाम और पता लिखिए जिन्हें हवाला का फेरना करत समय सुनवाई का अवसर देना चाहिए ।

नोट :- 1. कृपया हवाला -प्रावेदन पत्र की उम्मीद प्रतियां संलग्न कीजिए जिसने की उपर कथित व्यक्ति हो यह विनियम 41 के उपविनियम (1) की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

संलग्न दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना के आधार पर—

1. प्रावेदक एतद्वारा कम्पनी विधि बोर्ड, प्रधान न्यायपीठ/क्षेत्रीय न्यायपीठ को कम्पनी अधिनियम, 1956/प्रतिभूति अधिनियम के अन्तर्गत हवाला प्रस्तुत करती है । (यहां पर हवाले की प्रकृति का उल्लेख कीजिए)

2. आवेदक का निम्न निवेदन है :
(यहाँ पर मामले के संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन कीजिए।)
3. आवेदक के निवेदन निम्न प्रकार है :—

(निवेदन)

4. आवेदक ने जिन वस्तुओं या उनकी प्रतियों को संलग्न किया है वे नीचे निर्दिष्ट हैं।
5. आवेदक कम्पनी विधि बोर्ड के विशेष आदेश की प्रार्थना करता है :—
(यहाँ पर प्राप्ति आवेश की प्रकृति का वर्णन करें।)

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

वस्तुओं की सूची

- 1.
- 2.
- 3.

फार्म सख्या-4

(देखिये विनियम 37)

कम्पनी विधि बोर्ड (..... न्यायपीठ के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के सम्बन्ध में धारा 58क

एवं

(जमाकर्ता/आवेदक का नाम बताइये) के सम्बन्ध में

एवं

..... लिमिटेड के सम्बन्ध में (कम्पनी का नाम बताइये)

- (i) जमाकर्ता—आवेदक का नाम और पता
- (ii) कम्पनी का नाम और इसके रजिस्टर्ड कार्यालय का पता
- (iii) जमाकर्ता का नाम पूरे पते समेत
- (iv) जमाकर्ता

- (v) स्वयंजमा राशि की रसीद की संख्या और तारीख (फोटो प्रति संलग्न की जाये)
- (vi) जमा राशि कर शर्तों और जमा राशि की परिपक्वता की तारीख।
- (vii) कम्पनी द्वारा की गई अदायगी, यदि कोई हो, का विवरण।
- (viii) ग्रावेदन पत्र की तारीख पर वास्तविक देय राशि (मूलधन/व्याज)।
- (ix) कम्पनी और जमाकर्ता के बीच किए गए पत्र व्यवहार, यदि कोई हो, का विवरण।
(पत्र व्यवहार का प्रति संलग्न की जाये)
- (X) कोई अन्य विवरण जो समीचीन समझा जाये
- जमाकर्ता—ग्रावेदन प्रत्यूष प्रार्थना करता है:—
- (i) कि उपरोक्त नाम की कम्पनी को निदेश दिया जाये कि जमा राशि की शर्तों के अनुसार उपरोक्त जमा राशि को ध्याज समेत वापस करे।
- (ii) और ऐसे आने के आदेश पास किए जायें जिन्हें कम्पनी विधि ब्रोकर माने की परिस्थितियों में उचित समझे।

(ग्रावेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

नोट:—

1. ग्रावेदक पत्र के साथ पचास रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बतौर फीस संलग्न होगा जिसे खेतन एवं लेखा अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली बम्बई/कलकत्ता/मद्रास के नाम पर लिया जायेगा।
2. ग्रावेदन पत्र की दो प्रतियां दायर की जायेंगी।

अनुसूचक-III

एक याचिका के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(देखिये विनियम 18 एवं 34)

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	याचिका की प्रकृति	याचिका के अनुसूचक
1	2	3	4
1.	17(2)	कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की एक राज्य से दूसरे राज्य में या कम्पनी के उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी संगम ज्ञापन में संशोधन को पुष्ट करने हेतु याचिका।	<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम नियम की प्रति। 2. स्पष्टीकरण देते हुए वक्तव्य समेत मीटिंग बुलाने की नोटिस की प्रति। 3. कम्पनी के सदस्यों द्वारा संशोधन स्वीकार करते हुए विशेष संकल्प की प्रति। 4. उस समा की कार्रवाई का विवरण प्रलेख जिसमें विशेष संकल्प पारित किया गया है। 5. याचिका संस्थापित करने हुए शपथ पत्र। 6. ग्रावेदन शुल्क देने का माध्य दिखाने वाला बैंक ड्राफ्ट। 7. ब्रोकर के संकल्प समेत उपस्थिति का आपन या जैसा भी हो बकालतनामा। 8. लेखा परीक्षा की एवं निदेशकों की रिपोर्ट समेत कम्पनी की नथपत्र संपरीक्षित तुलनपत्र एवं लाभ-हानि खाता। 9. समाचार पत्रों की कतरन समेत नोटिस भेजने की पुष्टि करता हुआ शपथ पत्र।

1	2	3	4
			10. विनियम 36(7) के अनुसार लेनदारों की सूची को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र।
			11. कम्पनी रजिस्ट्रार क्षेत्रीय निवेशक और या राज्य सरकार के प्रधान सचिव/प्रशासक, जहाँ भी लागू होता हो, का पावती रखें। [विनियम 14(3) देखें]।
2. 18(4)	संशोधन के पंजीकरण हेतु दस्तावेजों को दायर करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन पत्र।		1. शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन पत्र। 2. आवेदन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट।
3. 17	धारा 17 के अन्तर्गत दिए गए आवेदन के स्वीकृतिकरण हेतु आवेदन पत्र।		1. विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्पित शपथ पत्र। 2. आवेदन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट।
4. 43	प्राइवेट कम्पनी बनाने वाली शर्तों के अनुपालन में असफलता के कारण उत्पन्न परिणामों से राहत की प्रार्थना करने वाली याचिका।		1. संगम स्थापन एवं नियमावली की प्रति। 2. यह दर्शाते हुए कि धारा 3 की उपधारा (i) के वाक्य (iii) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में शूक हुई है दस्तावेजों की प्रति। 3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 4. आवेदन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट। 5. बोर्ड के सदस्य समेत उपस्थिति स्थापन या जैसा हो, बकालतनामा।
5. 49(10)	निवेश के रजिस्ट्रार के निरीक्षण करने देने के लिए कम्पनी को निवेश देने हेतु याचिका यदि निरीक्षण करने से मना किया गया हो।		1. निवेश रजिस्ट्रार का कम्पनी द्वारा निरीक्षण मना करने को दर्शाते हुए दस्तावेजों साक्ष्य यदि कोई हो। 2. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 3. आवेदन शुल्क के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति स्थापन या जैसा भी हो बकालतनामा। 5. कम्पनी के साथ किया गया कोई अन्य समीचीन पत्र व्यवहार। 6. कम्पनी रजिस्ट्रार से पावती रखें [वेबिचे विनियम 14(4)]।
6. 58(9)	परिपक्व जमाशर्तों को वापस करने के लिए कम्पनी को निर्देश देने की याचिका।		1. जमाशर्तों की रसीद की प्रति। 2. कम्पनी के किए गए पत्र व्यवहार की प्रति। 3. आवेदन शुल्क के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट।
7. 79(2)	ब्रिस्कोउट पर शेयर जारी करने की अनुमति के लिए याचिका।		1. संगम स्थापन एवं नियमावली की प्रति। 2. स्वीकृतिकरण के व्यक्तित्व समेत मॉडिंग बुलाने की नोटिस की प्रति और निर्णय की अनुमति देने वाला संकल्प। 3. उस समीचीन कार्यवाही का प्रलेख जिसमें संकल्प पास किया गया। 4. पिछले तीन वर्षों की परिस्थित मुलपत्र तथा लाभ हानि खाता परीक्षाओं की रपट और निर्देशकों की रपट। 5. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 6. आवेदन पत्र की फीस देने के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का स्थापन या जैसा हो बकालतनामा।

1	2	3	4
8. धारा 80क (1) का परलुक्	अभुगतान योग्य प्रेफरेन्स शेयरों के बचने प्रतिरिक्त अभुगतान योग्य प्रेफरेन्स शेयरों का जारी करना।	1. संगम शापन और नियमावली की प्रति। 2. विद्यमान प्रेफरेन्स शेयरों के जारी करने की शर्तों की दशाति हुए दस्तावेज। 3. बोर्ड के संकल्प तथा साधारण सभा के संकल्प की प्रति जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रेफरेन्स शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है। 4. न्यूनतम परीक्षित तलपत्र तथा गान्ध्याति की संपरीक्षित प्रति संपरीक्षकों एवं निदेशकों की रपट के समेत। 5. याचिका को सत्यापित करता हुआ नपथ पत्र। 6. आवेदन पत्र की अदायगी का साक्ष्य देता हुआ बैंक ड्राफ्ट। 7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या वकालतनामा, जैसा भी हो। जहां कम्पनी याचिका कर्ता है :	1. संगम शापन और नियमावली की प्रति। 2. विद्यमान प्रेफरेन्स शेयरों के जारी करने की शर्तों की दशाति हुए दस्तावेज। 3. बोर्ड के संकल्प तथा साधारण सभा के संकल्प की प्रति जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रेफरेन्स शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है। 4. न्यूनतम परीक्षित तलपत्र तथा गान्ध्याति की संपरीक्षित प्रति संपरीक्षकों एवं निदेशकों की रपट के समेत। 5. याचिका को सत्यापित करता हुआ नपथ पत्र। 6. आवेदन पत्र की अदायगी का साक्ष्य देता हुआ बैंक ड्राफ्ट। 7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या वकालतनामा, जैसा भी हो। जहां कम्पनी याचिका कर्ता है :
9. 111	किसी भी आधार पर जिसमें शेयरों, डिबेंचरों के घन्-रण उत्तराधिकार परिवर्तन कम्पनी द्वारा इनकार शामिल होगा सदस्यों के रजिस्टर के सुधार के लिए याचिका।	1. संगम शापन एवं नियमावली की प्रति। 2. न्यूनतम संपरीक्षित तलपत्र, लाभ हानि खाता संपरीक्षकों तथा निवेश की रपट। 3. सदस्यों के रजिस्टर उद्यरण की प्राधिकृत प्रति। 4. बोर्ड या उसकी समिति के संकल्प की प्रति (जहां लागू होती हो) 5. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज। 6. याचिका को सत्यापित करने हुए नपथपत्र। 7. आवेदन पत्र की अदायगी के साक्ष्य स्वरूप बैंक ड्राफ्ट। 8. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या वकालतनामा जसा भी हो। 9. याचिका की दो प्रतिरिक्त प्रतियां। जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की गई है :	1. संगम शापन एवं नियमावली की प्रति। 2. न्यूनतम संपरीक्षित तलपत्र, लाभ हानि खाता संपरीक्षकों तथा निवेश की रपट। 3. सदस्यों के रजिस्टर उद्यरण की प्राधिकृत प्रति। 4. बोर्ड या उसकी समिति के संकल्प की प्रति (जहां लागू होती हो) 5. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज। 6. याचिका को सत्यापित करने हुए नपथपत्र। 7. आवेदन पत्र की अदायगी के साक्ष्य स्वरूप बैंक ड्राफ्ट। 8. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या वकालतनामा जसा भी हो। 9. याचिका की दो प्रतिरिक्त प्रतियां। जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की गई है :
		1. याचिका में दिए गए अक्षतव्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कम्पनी को शेयरों के अन्तरण हेतु लिखा गया पत्र या किसी शेयर पर अधिकार बचलने या डिबेंचरों पर अधिकार बदलने संबंधी पत्र तथा कम्पनी के इनका रिया खत की एक प्रति भी शरीक होगी। 2. कम्पनी द्वारा वापस किए गए दस्तावेजों की प्रति। 3. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज। 4. आवेदन पत्र को सत्यापित करता हुआ नपथ पत्र। 5. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 6. उपस्थिति शापन, वकालतनामा समेत। 6. याचिका की दो प्रति।	1. याचिका में दिए गए अक्षतव्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कम्पनी को शेयरों के अन्तरण हेतु लिखा गया पत्र या किसी शेयर पर अधिकार बचलने या डिबेंचरों पर अधिकार बदलने संबंधी पत्र तथा कम्पनी के इनका रिया खत की एक प्रति भी शरीक होगी। 2. कम्पनी द्वारा वापस किए गए दस्तावेजों की प्रति। 3. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज। 4. आवेदन पत्र को सत्यापित करता हुआ नपथ पत्र। 5. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 6. उपस्थिति शापन, वकालतनामा समेत। 6. याचिका की दो प्रति।

1.	2.	3.	4.
10. 113 (1)	डिबेंचरों के प्रमाण पत्र भेजने की अवधि बढ़ाने की याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र की प्रति। 2. अन्तरण पत्र, यदि है तो। 3. अन्तरण की अनुमति और, या अवधि बढ़ाने की बोर्ड की संकल्प की प्रति। 4. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ पत्र। 5. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 6. न्यूनतम संपरीक्षित ताल पत्र, लाभ हानि खाता, सम्परीक्षकों एवं निदेशकों की रपट समेत। 7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या वकालत-नामा जैसा भी हो।
11. 113(3)	गेयर डिबेंचर प्रमाण पत्रों को जारी करने का प्रावधान करने वाली धारा 113 की उपधारा (1) के अनुपालन में शूक संबंधी याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए आवंटन पत्र की प्रतिलिपि। 2. गेयर या डिबेंचरों के अन्तरण के लिए दिए जाने के बारे में दस्तावेजी सबूत। 3. कम्पनी के धारा 113 की उपधारा (1) की शूक को पूरा करने के बारे में दी गई नोटिस। 4. कोई अन्य समीचीन पत्र व्यवहार। 5. याचिका को सत्यापित करता शपथ पत्र। 6. आवेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या वकालत-नामा, जैसा भी हो।
12. 118(3)	म्यास डी की प्रति देने के लिए याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. म्यास डी जारी करने के लिए कम्पनी को लिखे गये पत्र की प्रति। 2. कम्पनी द्वारा इनकार के खत, यदि कोई हो, की प्रति। 3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 4. आवेदन पत्र की फीस देने के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 5. उपस्थिति ज्ञापन वकालतनामा की प्रति के समेत।
13. 14(1) एवं (3)	कम्पनी रजिस्ट्रार के पास समय बढ़ाने या एक ऋण के विवरण उसके संशोधन या सम्पूर्ण को दायर करने के देर की माफी के याचिका (ख)		<ol style="list-style-type: none"> 1. ऋण बनाने/संशोधित करने, जैसा भी हो, के करार की प्रति। 2. धारा 292 (1) (ख) या (ग) और धारा 292(1) (क), जैसा भी हो, के अन्तर्गत कल्पित संकल्प की प्रति। 3. अवसर की कतरन एवं शपथ पत्र। 4. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 5. आवेदन पत्र के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 6. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति-ज्ञापन, या जैसा भी हो वकालतनामा।
14. 144(4)	ऋण-सृजन के पत्र और ऋण के रजिस्टर का निरीक्षण करने की याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी द्वारा निरीक्षण देने से याचिकाकर्ता को इनकार करने का दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो। 2. याचिका को सत्यापित। 3. आवेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. उपस्थिति ज्ञापन तथा वकालतनामा की एक प्रति।

1	2	3	4
15. 163(6)	रजिस्टर और रिटर्न के निरीक्षण के निदेश देने के लिए याचिका।	1. याचिकाकर्ता को कम्पनी द्वारा निरीक्षण करने से इनकार का दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो। 2. याचिका को उत्पापित करने वाला शपथ पत्र। 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रमायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. उपस्थिति ज्ञान बकालत नामे के साथ।	
16. 167	वार्षिक साधारण सभा करने या बुलाने का निदेश देने के लिए याचिका।	1. आवेदन पत्र को उत्पापित करता हुआ आवेदन पत्र। 2. आवेदन पत्र की फीस भ्रमायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट।	
17. 186	एक साधारण सभा बुलाने (वार्षिक साधारण सभा के अलावा) को आदेश देने के लिए आवेदन पत्र।	1. आवेदन की हैसियत के सबूत में दस्तावेजी साक्ष्य। 2. याचिका उत्पापित करता हुआ शपथ पत्र। 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रमायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. उपस्थिति ज्ञापन बकालतनामों के समेत।	
18. 188(5)	यह आदेश देने के लिए आवेदन पत्र की प्रदत्त अधिकार का मान्यता पूर्वक मामलों या अनावश्यक प्रचार कर बुरूपयोग। किया जा रहा है और कम्पनी के खर्चों को अंशतः या पूर्ण रूपेण सम्पत्तियों द्वारा देने के आदेश देने के बारे में।	1. याचिका उत्पापित करने हुए शपथ पत्र। 2. आवेदन पत्र की फीस भ्रमायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 3. उपस्थिति-ज्ञापन	
19. 196(4)	मिनिट पुस्तिका के तत्काल निरीक्षण का आदेश देने या उसकी एक प्रति तत्काल जिसे जरूरी हो उस व्यक्ति को देने का निदेश देने के लिए याचिका	1. कम्पनी द्वारा याचिका कर्ता को निरीक्षण करने देने से इनकार करने सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो। 2. याचिका उत्पापित करते हुए शपथ-पत्र। 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रमा करने के साक्ष्य में ड्राफ्ट। 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा भी हो बकालतनामा।	
20. 219(4)	यह आदेश की मांगी गई तत्पर की प्रति और सम्पत्तियों की रपट सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल दी जाये पास करने के लिए याचिका।	1. कम्पनी द्वारा याचिका कर्ता को निरीक्षण करने देने से इनकार करना दर्शाते हुए दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो। 2. याचिका को उत्पापित करता हुआ शपथ पत्र। 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रमायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा भी हो, बकालतनामा।	
21. 225(3) परम्पुक	यह फैसला करने के लिए याचिका कि क्या सम्पत्तियों के अपने प्रतिवेदन को प्रचारित कराने और मीटिंग में बहाये जाने के अधिकार भाग हानि पूर्ण जीजों के अनावश्यक विज्ञापन द्वारा दु रूपयोग हो रहा है और कम्पनी के खर्च का आवेदन जो अंशतः या पूर्णतः निवर्तमान सम्पत्तियों द्वारा किया जाएगा।	1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने देने से इनकार करना दर्शाते हुए, दस्तावेजी सबूत यदि कोई हो। 2. याचिका उत्पापित करता हुआ शपथ पत्र। 3. आवेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा भी हो बकालतनामा।	

1	2	3	4
22. 235(2)	एक आदेश द्वारा यह घोषित करने के लिए याचिका कि कम्पनी के कार्यों की निरीक्षण/निरीक्षकों द्वारा जांच कराई जाय ।	1. याचिका में कहे गए बक्तव्यों के समर्थन में दस्तावेजी और/या अन्य सबूत जो उचित रूप में याचिकाकर्ता/कर्ताओं को उपलब्ध हों । 2. याचिकाकर्ता/कर्ताओं की योग्यता एवं हैमियत के सम्बन्ध में दस्तावेजी सबूत प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति समेत । 3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 4. आवेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 5. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा हो, बकालतनामा । 6. याचिका की तीन अतिरिक्त प्रतियां ।	
23. 250	कतिपय शेयरों के तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत	1. शिकायत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो । 2. शिकायत को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 3. आवेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 4. बोर्ड की संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन या बकालतनामा ।	
24. 284(4) परन्तु	इस बात का फैसला करने के लिए याचिका कि क्या एक निवेशक का अपने प्रतिवेदन को प्रसारित करवाने और सभा में पक्षधर के अधिकार का मानहानि पूर्ण मामले की अनावश्यक विज्ञापन कराने के लिए दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और आवेदन पत्र करने पर कम्पनी को खर्च का आदेश देना ओ अंशतः या पूर्णतया इस प्रकार के निवेशक द्वारा देय होगा ।	1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने देने से इन्कार का दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो । 2. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रदा करने साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 4. उपस्थिति ज्ञापन बोर्ड संकल्प की प्रति समेत या बकालतनामा ।	
25. 304(2) (ख)	धारा 303 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर का तत्काल निरीक्षण का निवेश करने का आवेदन पास करने के लिए याचिका ।	1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण न करने देने के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो । 2. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 3. आवेदन पत्र की फीस भ्रदा करने के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 4. बोर्ड की संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन या बकालतनामा, जैसा भी हो ।	
26. 307(9)	इस धारा के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर का तत्काल निरीक्षण का निवेश पास करने के लिए याचिका	1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने देने के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो । 2. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 3. आवेदन पत्र की फीस की भवायगी में बैंक ड्राफ्ट । 4. उपस्थिति ज्ञापन बोर्ड के संकल्प की प्रति समेत या बकालतनामा ।	
27. 397, 398 400, 401, 402, 403, 404, 405	अत्याचार और/या कुप्रबन्ध को रोकने के सम्बन्ध में शक्तियों के प्रयोग के लिए याचिका	1. याचिका में बताए गए बक्तव्यों के समर्थन में दस्तावेज और/या अन्य साक्ष्य जो उचित रूप से याचिकाकर्ता को उपलब्ध हों । 2. याचिकाकर्ता/कर्ताओं की योग्यता एवं हैमियत के सम्बन्ध में प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति समेत दस्तावेजी सबूत । 3. जहाँ याचिका सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती हो, उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र ।	

1	2	3	4
			<p>4. नाम, पते धारित अंशों की संख्या और क्या उन सदस्यों द्वारा जिन्होंने अपने बिना पर याचिका प्रस्तुत करने के लिए सहमति दी है शेषों पर वेय समस्त आह्वान राशि दे दी गई है। यथाति हुए विवरणों का विवरण पत्र।</p> <p>5. जहाँ पर कोई याचिका धारा 399 (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के सदस्य या सदस्यों को प्राधिकृत करने का आदेश इसी प्रकार याचिका के साथ संलग्न किया जाएगा।</p> <p>6. याचिका सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र।</p> <p>7. आवेदन पत्र की फीस प्रवा करने के साथ में बैंक ड्राफ्ट।</p> <p>8. बोर्ड के संकल्प पत्र समेत उपस्थिति ज्ञापन पत्र।</p> <p>9. याचिका की तीन अनिवार्य प्रतिया।</p>
28. 407(1)(ख)	<p>एक प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक की जिम्मा करार समाप्त कर दिया गया है या निरस्त गया है वगैरह की केन्द्रीय सरकार पर नोटिस तामीन की गई है, नियुक्ति का अनुमति स्वीकृत करने के याचिका।</p>	<p>1. याचिका में कहे गए अभिवचनों के समर्थन में वस्तावेजी और/या अन्य सबूत जो याचिकाकर्ता/कर्ताओं के उचित रूप से उपलब्ध हों।</p> <p>2. प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति सहित या याचिका-कर्ता (कर्ताओं) की योग्यता और हैसियत सम्बन्ध में दस्तावेजी सबूत।</p> <p>3. जहाँ याचिका सदस्यों की तरफ से दी जाती है, उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र।</p> <p>4. नाम, पते, धारित अंशों की संख्या और या उन सदस्यों द्वारा जिन्होंने, अपने बिना पर याचिका दाख करने की सहमति दी है अंशों के समस्त आह्वान राशि या अन्य राशियों दे दी है, यथाति हुए विवरण पत्र।</p> <p>5. जहाँ पर याचिका केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 399(4) के अन्तर्गत प्राधिकृत किसी सदस्य या सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत की जाती है अंशों केन्द्रीय के इस प्रकार के सदस्य या सदस्यगण को प्राधिकृत करने का आदेश इसी प्रकार संलग्न होगा।</p> <p>6. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र।</p> <p>7. आवेदन पत्र की फीस की प्रदायगी के साथ में बैंक ड्राफ्ट।</p> <p>8. बोर्ड के संकल्प की प्रति सहित उपस्थिति शपथ या वकालतनामा।</p>	
29. 408(1) और (5)	<p>यह फैसला करने हेतु याचिका कि क्या निदेशकों के बोर्ड में सरकारी निवेशक नियुक्त करना जरूरी है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।</p>	<p>1. याचिका में कहे गए अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेजी और/या अन्य सबूत जो याचिकाकर्ता (कर्ताओं) को उचित रूप से उपलब्ध हों।</p> <p>2. प्रत्येक कीमत सहित समेत याचिका कर्ता (कर्ताओं) की योग्यता और हैसियत के बारे में वस्तावेजी सबूत,</p> <p>3. याचिका को सत्यापित करना हुआ शपथ पत्र।</p> <p>4. आवेदन पत्र की फीस प्रदायगी के साथ में बैंक ड्राफ्ट।</p> <p>5. बोर्ड के संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति विज्ञापन या वकालतनामा,</p> <p>6. याचिका की तीन अनिवार्य प्रतिया।</p>	

1	2	3	4	5
40. 409 (1)		कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की सम्भावना रखने वाले निदेशकों के बोर्ड में परिवर्तन को रोकने के लिए याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. याचिका में कहे गए अधिवक्त्रों के समर्थन में दस्तावेजी और या अन्य साबूत जो याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता को उचित रूप में उपलब्ध हों। 2. प्रत्येक की मत सहित सभेस याचिका कर्ता/कर्ताओं की योग्यता और हैसियत के बारे में दस्तावेजी सहित साबूत, 3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 4. आवेदन पत्र की फीस प्रयायनी के साध्य में बैंक ड्राफ्ट 5. बोर्ड के संकल्प की पूर्ति समेत उपस्थिति विज्ञापन या वकालतनामा। 6. याचिका की तीन अतिरिक्त प्रतियां।
31. 614 (1)		रजिस्ट्रार की रिटर्न अधि भेजने में चूक को पूरा करने के लिए कम्पनी को निदेश देने के बारे में आदेश पाग करने के सम्बन्ध में याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी पर चूक को पूरा करने के लिए सामीलकी गई नोटिस की पूर्ति। 2. नोटिस तामिल करने का दस्तावेजी साबूत। 3. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ पत्र। 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति विज्ञापन या जैसा हो वकालतनामा। 5. आवेदन पत्र की फीस की प्रयायनी के साध्य बैंक ड्राफ्ट।
32. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22क (4) (ग)		प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के बारे में निदेश जारी करने के लिए हवाला।		<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेज। 2. अन्तरणकर्ता/जिसे अन्तरण किया गया हो/स्टाक बलाल/सम्बन्धित स्टोक एक्सचेंज से किए गए पत्र व्यवहार की प्रतियां। 3. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पत्र की प्रमाणित प्रति। 4. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 क की उपधारा (4) के बाध्य (ख) के अन्तर्गत अन्तरण-कर्ता/अन्तरण्य को दी गई नोटिस। 5. निदेशकों ने बोर्ड द्वारा अन्तरण को पंजीकृत करने हन्कार करने का कारण बताते हुए संकल्प। 6. संगम-ज्ञापन तथा नियमावली तथा सम्परोधि नम्र्यतम तालपत्र और लाभहानि खाते की तीन प्रतियां। 7. कम्पनी की हैसियत के बारे में दस्तावेजी साबूत। 8. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 9. आवेदन पत्र की फीस के साध्य में बैंक ड्राफ्ट। 10. बोर्ड के संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन। 11. हवाला के अनुलग्नको समेत दो अतिरिक्त प्रतियां
33. एकाधिकार समूह अधिनियम की धारा (2)क		अन्तर्सम्बन्ध या एक ही प्रबंध जैसे प्रश्नों का एकाधिकार अधिनियम की धारा (2) क के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करने का याचिका।		<ol style="list-style-type: none"> 1. याचिका में कहे गए अधिवक्त्रों के समर्थन दस्तावेजी सत्य जो याचिकाकर्ता (कर्ताओं) को उचित रूप से उपबन्ध हों। 2. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र। 4. आवेदन पत्र के साध्य में बैंक ड्राफ्ट। 4. याचिका को तीन अतिरिक्त प्रतियां।

दिप्पणी—ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक दस्तावेज की प्रति सत्य प्रति लिपि के रूप में प्राधिकृत और प्रमाणित होनी चाहिए।

COMPANY LAW BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1991

G.S.R. 291(E) --In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, commencement and interpretation.—

(1) These regulations may be called the Company Law Board Regulation, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies to the interpretation of these regulations as it applies to the interpretation of a Central Act.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(b) “Annexure” means an Annexure to these regulations;

(c) “application” means an application by which an interlocutory proceeding is commenced before a Bench;

(d) “authorised representative” means a person authorised in writing by a party under sub-regulation (2) of regulation 19 to function before a Bench as the representative of such party;

(e) “Bench” means a Bench of the Board formed under sub-section (4B) of Section 10E of the Act;

(f) “Bench Officer” means an officer notified by the Board for the purpose of—

(i) receiving, examining and processing of applications; and

(ii) performing such other function as may be entrusted to him by or under these regulations.

(g) “Board” means the Board of Company Law Administration, constituted under Section 10E of the Act;

(h) “Certified” means, in relation to a copy, certified as provided in section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872);

(i) “Chairman” means Chairman of the Board;

(j) “Company” includes a foreign company;

(k) “filed” means filed in the office of the Bench;

(l) “Form” means a form specified in Annexure II;

(m) “Member” means a member of the Board;

(n) “The Monopolies Act” means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(o) “Office of the Bench” means the office of the Bench Officer ;

(p) “party” means a person who files an application or petition before a Bench, the respondent, the Registrar of Companies or the Regional Director and includes any person who has a right under the Act to make suggestions or objections,

(q) “Petition” means an application, appeal or complaint in pursuance of which any proceeding, not being an interlocutory proceeding is commenced by the Bench ;

(r) “Reference” means a reference within the meaning of regulations 35, 40 and 42 of these regulations;

(s) “Regional Director” means a person appointed by the Central Government as a Regional Director for the purposes of the Act;

(t) “Registrar” means Registrar of Companies appointed under the Act,

(u) “sealed” means sealed with the seal of the ‘Board’ or ‘Bench’;

(v) “Secretary” means Secretary to the Board and includes “Under Secretary” to the Board and any other officer, by whatever name called, to whom powers and duties of Secretary may be entrusted under regulation 31,

(w) “Section” means a section of the Act;

(x) “Securities Act” means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(2) Words or expressions occurring in these regulations and not defined in sub-regulation (1) shall bear the same meaning as in the Act.

CHAPTER II

General

3. Composition of Benches of the Board.—(1) Subject to regulation 4, every Bench of the Board formed under sub-section (4B) of Section 10E may consist of one or more members.

(2) The order of the Chairman forming any Bench shall specify therein the powers which shall be exercised and functions which shall be discharged by the Bench.

(3) The Chairman shall, in relation to each Bench formed specify the member of the Bench before whom every matter requiring decision of the Board (not being a matter affecting the final disposal of the petition) shall be placed for orders and in the absence of the member so specified every such matter shall be

placed before any other member of the Bench who is present.

Power of the Chairman to specify matters which may be dealt with by a Bench.

4. (1) It shall be lawful for the Chairman to provide that matters falling under sections 235, 237, 247, 248, 250, 388B, 408 and 409 and matter falling under Chapter VI of Part VI of the Act and under section 2A of the Monopolies Act and all other matters incidental thereto shall be dealt with by a Bench consisting of not less than two members including the Chairman (which shall be known as the Principal Bench).

(2) The Principal Bench shall be at New Delhi but the Principal Bench may sit at such places in India and at such time as may be most convenient in exercise of its powers and functions in India.

(3) It shall be lawful for the Chairman to provide that matters falling under sections 111 and 269 of the Act and under section 22A of the Securities Act shall be dealt with by a Bench consisting of not less than two members and all other matters not falling under sub-regulations (1) and (3) of this regulation including issuing of directions and interlocutory matters may be dealt with by a Bench consisting of a single member.

5. Vacancy in the office of the Chairman.—If, for any reason, the Chairman is not appointed or a casual vacancy occurs in the office of the Chairman, the seniormost member of the Board, holding office of member for the time being, shall discharge the functions of the Chairman until a person is appointed as the Chairman.

6. Inability of the Chairman to function.—When the Chairman is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the seniormost member of the Board, if so authorised by the Chairman, shall discharge functions of the Chairman until the day on which the Chairman resumes the charge of his functions.

7. Jurisdiction of the Bench.—(1) All proceedings, other than the proceedings before the Principal Bench under regulation 4, shall be instituted before the Bench which in whose jurisdiction the registered office of the company is situated.

(2) The regions where the Benches shall ordinarily have their sittings are the Northern Region, the Southern Region, the Eastern Region and the Western Region, the States and Union Territories falling within each of such region being States and Union Territories as provided in Annexure I to these regulations.

(3) The Benches shall ordinarily have their sittings at Calcutta (Eastern Region), Bombay (Western Region), Madras (Southern Region) and New Delhi (Northern Region) :

Provided that the Bench may, at its discretion, hold its sittings in any other city or town falling within the region.

8. Language of the Bench.—(1) The proceedings of a Bench shall be conducted in English or Hindi.

(2) No petition, application, reference, document or other matter contained in any language other than English or Hindi shall be accepted by the Board unless the same is accompanied by a true translation thereof in English or Hindi.

(3) All documents required to be translated into English or Hindi shall be translated by a person appointed or approved by the Board :

Provided that any translation which is agreed to by the parties to the proceedings may be accepted by the Board in appropriate cases as a true translation.

(4) All final and interlocutory orders of the Bench shall be in English or Hindi.

9. Sitting hours of the Bench.—Sitting hours of the Bench shall ordinarily be from 10.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 2.30 p.m. to 4.30 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and other public holidays, subject to any general or special order made by the Chairman.

10. Bench to have seal of its own.—(1) There shall be a separate seal of a Bench of the Board.

(2) Every such seal shall be kept in the custody of the Secretary or Bench Officer and shall be used under his direction or control.

(3) Every order or communication made, notice issued or certified copy granted by a Bench shall be stamped with the seal of the concerned Bench and shall be authenticated by the Secretary or the Bench Officer, as the case may be.

11. Petitions, etc., to be in writing.—(1) Every affidavit application, reference or petition shall be written, typewritten, cyclostyled or printed, neatly and legibly, on one side of the substantial paper of foolscap size in double space and separate sheets shall be stitched together and every page shall be consecutively numbered.

(2) Numbers and dates specified in any affidavit, application, reference or petition shall be expressed in figures as well as in words; and, where the date specified therein has not been stated according to the Gregorian Calendar, the corresponding date according to the Gregorian Calendar shall also be specified.

12. Application, reference or petition to be divided into paragraphs.—Every application, reference or petition shall be divided into separate paragraph which shall be numbered serially and shall state thereon the matter, and the name of the company, to which it relates.

13. General heading to be in Form No. 1 in Annexure-II.—The general heading in all proceedings, whether original or interlocutory, and of advertisements and notices, shall be as in Form No. 1 in Annexure-II.

14. Procedure for filing petition.—(1) Subject to the provisions of regulations 35 and 37, a petition to the Bench shall be prepared in Form No. 1 in Annexure-II and presented by the petitioner in person or through authorised representative to the office of the Bench or be sent by registered post with acknowledgement due addressed to the Secretary or Bench Officer of the Bench concerned, as the case may be.

(2) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the petition as there are respondents shall be furnished by the petitioner;

Provided that where the number of respondents is more than five, the Secretary or Bench Officer may permit the petitioner to file extra copies of the petition at the time of issue of notice to the respondents.

(3) The petitioner shall serve a copy of the reference or petition other than a petition under sections 49, 79, 80A, 111, 113, 118, 163, 188, 196, 219, 225, 284, 304 and 307 of the Act and Section 22-A of the Securities Act, upon the concerned Registrar of Companies having jurisdiction over the company and shall attach to and present with his petition, reference, an acknowledgement from the office of the Registrar of Companies receiving a copy of the petition, reference so served :

Provided that, in the case of a petition under section 17 by a company licensed under section 25 of the Act, the copy of the petition shall also be served upon the Regional Director :

Provided further that, in case of a petition or complaint under sections 235, 237, 250, 397, 398, 408 and 409 of the Act; a copy thereof shall also be served upon the Central Government.

(4) (a) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (2), the Bench may permit more than one person to join together and file a single petition if it is satisfied, having regard to the cause of action and the nature of relief prayed for, that they have a common interest in the matter.

(b) Such permission shall be granted where the joining of the petitioners by a single petition is specifically permitted by the Act.

(5) Every petition other than an application under section 58A(9) of the Act, shall be accompanied by an affidavit verifying the same and shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and complete residential address of the deponent and shall be signed by the deponent and sworn before the person specified in section 558 of the Act.

(6) Where the deponent is not personally known to the person before whom the affidavit under sub-regulation (5) is sworn, he shall be identified by a person who is known to the person before whom the affidavit is sworn.

(7) Every affidavit under sub-regulation (5) shall clearly and separately indicate the statements which are true to the —

- (a) knowledge of the deponent;
- (b) information received by the deponent;
- (c) belief of the deponent; and
- (d) information based on legal advice.

(8) Where the statement referred to in sub-regulation (7) is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also include the name and complete residential address of the person from whom the information has been received by the deponent and whether the deponent believes that information to be true.

15. Presentation and scrutiny of petition.— (1) The Office of the Bench shall endorse on every petition the date on which it is presented.

(2) If, on scrutiny, the petition is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) If the petition, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Secretary or Bench Officer may allow the party to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Secretary or Bench Officer may allow the petitioner such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) Where the petitioner is aggrieved by the order made by the Secretary or Bench Officer under sub-regulation (3), the matter shall be placed before the Bench for its order and it shall be competent for a single member of the Bench to issue necessary direction which shall be deemed to be the direction of the Bench.

16. Contents of petition.—Every petition, other than an application filed under regulation 37 shall set forth the name of the Company, with its status, date of incorporation, the address of its registered office, authorised capital, paid-up capital with division of different classes of shares and terms of issue, if any, in the case of preference shares, main objects in brief, for which the company was formed, present business activities of the company, and shall also set forth concisely under distinct heads the grounds for such petition and the nature of relief(s) prayed for.

17. Contents of interlocutory application.— An application filed subsequent to the filing of the petition applying for any interim order or direction shall as far as possible, be in Form No. 2 in Annexure-II and shall be accompanied by an affidavit verifying the application in the manner laid down in regulation 14.

Provided that it shall not be necessary to present a separate application to seek an interim relief or direction, except for condonation of delay in filing the petition, if, in the original petition, the same is prayed for.

18. Documents to accompany the petition.—(1) A petition shall be accompanied by documents as prescribed in Annexure-III and shall be accompanied by an Index of Documents.

(2) Documents referred to in sub-regulation (1) may be attested by the authorised representative and the documents shall be marked serially as Annexure A1, A2, A3 and so on.

(3) Where the petition is filed by the authorised representative, memorandum of appearance shall be appended to the petition :

Provided that where the petition is filed by an advocate, it shall be accompanied by a duly executed Vakalatnama.

19. Rights of a party to appear before the Bench.— (1) Every party may appear before a Bench in person or through an authorised representative.

(2) A party may, by writing, authorise an advocate or a Chartered Accountant or a cost and Works Accountant or a Company Secretary or a Secretary in whole-time practice to function as the representative of such party. A company may also appoint a director of the company to appear, duly authorised in this behalf, in a proceeding before the Bench.

20. Plural remedies.—A petition shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

21. Service of notice and process issued by the Bench.—(1) Any notice or process to be issued by the Bench may be served by any of the following modes directed by the Bench :

- (i) Service by the party itself.
- (ii) by hand delivery (dasti) through a messenger of the Office of the Bench;
- (iii) under certificate of Posting;
- (iv) by registered post with acknowledgment due if so required by an order of the Bench;
- (v) where the Central Government is a party, though the Secretary of the concerned Ministry or Department or through Branch Secretariat of the Ministry of Law or through Standing Counsel of the Central Government;
- (vi) where the State Government is a party, through the Chief Secretary or the Standing Counsel of the State Government.

(2) Where a notice is required to be served on a company, it shall be served in the manner specified in section 51 or, in the case of a foreign company, in the manner specified in section 596, and may also be served in such other manner as the Secretary or the Bench Officer may direct.

(3) Save as otherwise provided in sub-regulation (2), notices and other documents, which are required to be served on any person, other than a company, shall be served by delivering or tendering a copy thereof to such person or his authorised representative, where he appears by such representative or by prepaid registered post, acknowledgment due, addressed to the last-known address of such person.

(4) Where a notice is served by the registered post, the Secretary or Bench Officer may, if the acknowledgement is not received, determine the question as to the sufficiency of the service of the notice.

(5) Where the notice sent by registered post is returned by the post office with the remarks "refused", the notice may be presumed to have been duly served.

(6) Every notice, of the petition or reference issued by the Bench shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the petition or reference, as the case may be.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (6), where, for any reason whatsoever, it is not reasonably practicable to serve notice of petition on all the respondents, the notice may be

served by public advertisement, as the Bench may in each case direct, for the protection of the interests of the shareholders, creditors or any class of them.

(8) The Bench shall, in such cases, determine who shall bear the cost of the public advertisement.

22. Filing of reply and other documents by the respondents (1) Each respondent intending to contest the petition shall file, in triplicate, the reply to the petition and the documents relied upon with the office of the Bench within such period as may be fixed by the Bench but not exceeding fifteen days of service of petition upon him.

(2) In the reply filed under sub-regulation (1), the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated by the petitioner in his petition and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case. The reply so filed shall be signed and verified in the manner as provided in regulation 14.

(3) The documents referred to in sub-regulation (1) shall also be filed along with the reply and the same shall be marked as Annexures R1, R2, R3 and so on.

(4) The respondents shall also serve a copy of the reply along with the documents mentioned in sub-regulation (1), duly attested to be true copies on the petitioner or his authorised representative, if any, and file proof of such service with the Office of the Bench.

(5) The Bench may, if so satisfied, allowed filing of the reply after the expiry of the prescribed period, on sufficient cause being shown.

23. Filing of counter-reply by the petitioner.—Where the respondent states such additional facts as may be necessary for the just decision of the case under sub-regulation (2) of regulation 22, the Bench may allow the petitioner to file a counter-reply to the reply filed by the respondent. The procedure laid down in regulation 22 shall apply, mutatis mutandis, to the filing of such counter-reply.

24. Power of the Bench to call for further information/evidence. The Bench may, before passing orders on the petition, require the parties or any one or more of them, to produce such further documentary or other evidence as the Bench may consider necessary—

- (a) for the purpose of satisfying itself as to the truth of the allegations made in the petition; or
- (b) for ascertaining any information which, in the opinion of the Bench, is necessary for the purpose of enabling it to pass orders on the petition.

25. Hearing of petition.—The Bench may, if sufficient cause is shown at any stage of the proceeding, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the petition or the application. The Bench may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by such adjournment.

26. Procedure to be followed where any party does not appear.—(1) Where, on the date fixed for hearing of the petition or any application or on any other date to which such hearing may be adjourned, the petitioner or the applicant as the case may be, does not appear when the petition or the application is called for hearing, the Bench may, in its discretion, either dismiss the petition or the application for default or hear and decide the same ex-parte.

(2) Where a petition or application has been dismissed for default and the petitioner or the applicant files an application within thirty days from the date of dismissal and satisfies the Bench that there was sufficient cause for his non-appearance when the petition or the application was called for hearing, the Bench may pass an order setting aside the order dismissing the petition or the application and restore the same :

Provided, however, where the case was disposed of on merit, the decision shall not be recalled.

(3) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, the petition appears but the respondent does not appear when the petition is called for hearing, the Bench, may, in its discretion, adjourn the hearing or hear and decide the petition ex-parte.

(4) Where the petition has been heard ex-parte against the respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Bench within thirty days for an order to set aside and if the respondent and respondents satisfy the Bench that the notice was not duly served on him or them or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the petition was called for hearing, the Bench may make an order setting aside the ex-parte order against him or them on such terms as it thinks fit and shall appoint a date for proceeding with the petition :

Provided that where the ex-parte order is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by sub-regulation (7) of regulation 21, the Bench shall not set aside the ex-parte order merely on the ground that a shareholder or an creditor did not have the notice of the petition.

27. Review.—(1) Any party considering itself aggrieved by an order made by the Bench on account of some mistake or error apparent on the face of the record desires to obtain a review of the order made against him, may apply for a review of the order to the Bench which had made the order.

(2) No application for review shall be made after the expiry of a period of sixty days from the date of the order and no such application shall be entertained unless it is accompanied by an affidavit verifying the application in the manner laid down in regulation 14.

(3) Where it appears to the Bench that there is no sufficient ground for a review, it shall reject the

application but, where the Bench is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same :

Provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party to enable him to appear and to be heard in support of the order, a review of which is applied for.

28. Substitution of legal representative.—(1) In the case of death of any party during the pendency of the proceedings before the Bench, the legal representatives of the deceased party may apply within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(2) Where no application is received within the period specified in sub-regulation (1), the proceedings against the deceased party shall abate :

Provided that, on good and sufficient reasons, the Bench, on application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

29. Order of the Bench.—(1) Every order of the Bench shall be in writing and shall be signed by the member or members constituting the Bench which pronounces the order.

(2) Any order of the Bench deemed fit for publication in any journal, authoritative report or the Press may be released for such publication on such terms and conditions as the Board may specify by general or special order.

(3) A copy of every interim order granting or refusing or modifying interim relief and final order passed on any petition or reference shall be communicated to the petitioner or the applicant and to the respondents and other parties concerned free of cost :

Provided that in the case of an order under section 17 confirming change of registered office, two copies of the order shall be supplied to the petitioner company free of cost.

(4) If the petitioner or the applicant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding, the same shall be supplied to him on such terms and conditions and on payment of such fee as may be fixed by the Bench by general or special order.

(5) The Bench may make such order or give such direction as may be necessary or expedient to give effect to its order or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

(6) It shall be lawful for a Bench to fix, and award, costs to any of the parties before it where it is of opinion that the award of such costs is necessary.

30. Inspection of records and supply of certified copies.—(1) Records of every pending proceedings will be open, as of right, to the inspection of the parties or their authorised representatives, on making an application in writing and on payment of a fee of Rs. 10 per day.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of Regulation 29, a person who is not a party to the proceedings, may after the final orders are passed, for sufficient reasons shown to the satisfaction of the Bench obtain copies of the petitions, replies and counter-replies on payment of such fee, as may be fixed by the Bench by general or special order.

(3) A person, who is not a party to the proceedings, may also obtain, as of right, at any time after the final orders are passed by the Bench, copies of the orders, on payment of such fee, as may be fixed by the Bench by general or special order.

(4) A person, who is not a party to the proceedings, has, however, no right to inspect the records of the proceedings or to obtain copies of the Exhibits put in evidence, except with the consent of the person by whom they were produced or under the orders of the Bench.

31. Power and Functions of the Secretary.—(1) The Secretary shall be the Principal Officer of the Board and shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Chairman.

(2) The Board, in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary, as it may deem fit, and the Secretary, shall be bound to assist the Board.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of this rule, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, namely,—

- (a) The Secretary shall have the custody of the records of the Principal Bench.
- (b) The Secretary shall receive all petitions, applications or references pertaining to the Principal Bench.
- (c) The Secretary shall assist the Principal Bench in the proceedings relating to the powers exercised by the Principal Bench.
- (d) The Secretary shall have the power to call for information, records and to inspect or cause to be inspected the records of other Benches.
- (e) The Secretary shall authenticate the orders passed by the Principal Bench.
- (f) The Secretary shall ensure compliance of the orders passed by the Principal Bench and other Benches.
- (g) The official seal of the Board shall be in the custody and control of the Secretary.
- (h) The Secretary shall have the right to collect from the Central Government or other offices, companies and firms, or any other persons such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Board under the Act and place the said information before the Board.

32. Powers and duties of the Bench Officer.—(1) In addition to the powers conferred elsewhere in these Regulations, the Bench Officer shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the Bench concerned, namely :—

- (i) to receive all petitions or applications and other documents including transferred applications;
- (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the petitions and applications before they are registered;
- (iii) to require any petition or application presented to the Bench to be amended in accordance with the Act and the regulations;
- (iv) Subject to the direction of the Bench, to fix the date of first hearing of the petitions or applications or other proceedings and issue notices thereof;
- (v) to direct any formal amendment of records;
- (vi) to order grant of copies of documents to parties to the proceedings;
- (vii) to grant leave to inspect the records of the Bench;
- (viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, applications for the issue of fresh notices and extending the time for filing such applications and to grant time not exceeding fifteen days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the matter before the Bench for appropriate orders after the expiry of the aforesaid period;
- (ix) to receive applications within thirty days from the date of death for substitution of authorised representatives of the deceased parties during the pendency of the petition or application;
- (x) to receive and dispose of applications for substitution except where the substitution would involve setting aside an order of abatement.
- (xi) to receive and dispose of applications by parties for return of documents.

(2) An appeal against any decision by a Bench Officer under clause (ii), (iii), (v) and (vii) shall be made to the Secretary by the aggrieved party within fifteen days from the date such decision is communicated to him and the decision thereon of Secretary shall be final.

33. Registers of petitions and applications.—(1) There shall be kept in the office of the Bench two separate registers, one for the petitions and the other for the applications filed before the Bench.

(2) In every register, referred to in sub-regulation (1), there shall be entered the following particulars, namely,—

- (a) the serial number of the petition or application and in addition, in the case of an application the serial number of the petition to which it relates;

- (b) the date of presentation or receipt of the petition or application;
- (c) the name of the company to which the matter relates;
- (d) the name and address of the petitioner or applicant;
- (e) the names and addresses of the other parties to the petition or application and the names and addresses of the authorised representatives of the parties, if any;
- (f) the provision of law under which the petition or application is made;
- (g) the nature of the reliefs which have been sought;
- (h) the date of disposal of the petition or application;
- (i) the nature of the order made by the Bench;
- (j) the date when the formal order is drawn up and communicated to the parties;
- (k) review, if any.

(3) Separate registers shall be opened for each year and each register of petitions shall be preserved permanently and each register of application shall be preserved for a period of eight years.

34. Fees.—(1) In respect of the several matters mentioned in Annexure III, there shall be paid fee for every petition as prescribed.

Provided that no fee shall be payable or shall be liable to be collected on a petition filed or reference made by the Registrar of Companies, Regional Director or by any officer on behalf of the Central Government.

Provided further that no fee shall be payable or shall be liable to be collected in respect of any matter in respect of which proceedings are initiated by the Board on its own motion;

(2) Fee as the prescribed shall be levied and collected on every interlocutory application.

Provided that no fee shall be payable or shall be liable to be collected on an application filed by the Registrar of Companies, Regional Director or by any officer on behalf of the Central Government.

(3) In respect of a petition or application filed before the Principal Bench or the Northern, Eastern, Southern and Western Regional Benches of the Board, fees payable under these regulations shall be paid by means of a bank draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi/Catcutta/Madras/Bombay, as the case may be.

CHAPTER III

Special provisions relating to certain specific matters;

Reference to Company Law Board.

35. Any reference to the Board by the Registrar of Companies under section 621A of the Act or any reference to the Board by the Central Government

under section 250, 269, 388-B and 408 of the Act or any reference by a company under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Act shall be made by way of an application in Form No. 3, and shall be accompanied by documents mentioned in Annexure III.

36. Petition under Section 17.—(1) The company shall, not less than one month before filing any petition under sub-section (2) of section 17,—

- (i) publish a general notice at least once in the daily newspaper published in the regional language of the State in which the registered office of the company is situated, and at least once in English, in a daily newspaper published in the English language and circulating in that State clearly indicating therein the substance of the petition and stating that any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the memorandum may intimate to the Bench Officer within twenty-one days of the date of the publication of the notice, the nature of interest and the grounds of opposition; and

- (ii) serve, by certificate of posting, individual notice(s) to the fact set out in clause (i) above on each debenture-holder and creditor of the company, unless otherwise required by the Bench to be sent by registered post.

(2) Where the petition seeks to change the registered office of the petitioner-company from one State to another, a notice together with the copy of the petition shall also be served by registered post on the Chief Secretary to the Government of the State in which the registered office of the petitioner company is situated, or, where the registered office of company is situated in a Union Territory, to the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory.

(3) Any person intending to oppose the petition shall within twenty-one days from the date of service or publication of the notice, as the case may be, deliver, or cause to be delivered, or send by registered post, the objections supported by an affidavit, in original, to the Bench Officer and shall serve a copy of the objections on the petitioner-company at its registered office.

(4) If default is made in complying with any provision of sub-regulation (3), the person concerned shall be deemed to have consented to the alteration proposed in the petition.

Provided that the Bench, may, if it thinks fit even after the final hearing, permit any person to file objections after giving notice to the petitioner-company.

(5) The petitioner-company shall prove the despatch publication and service of notice(s) by an affidavit and such affidavit shall be enclosed with the petition.

(6) A petition under section 17 shall invariably contain information relating to the number of creditors and the total amount due to them upto the latest practicable date preceding the date of filing of the petition and in any case, the date of which the list referred to in sub-regulation (8) is made up, shall not

precede the date of filing the petition by more than two months. A list of creditors and debenture-holders shall also be filed along with the petition.

(7) The Secretary of the petitioner-company, if any and not less than two directors of the company one of whom shall be a managing director, where there is one, shall file an affidavit to the effect that they have made a full enquiry into the affairs of the company and, having done so, have formed the opinion that the list referred to in sub-regulation (8) is correct, that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on a contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims included in the list are borne out by the books and records of the company and that there are no other debts of, or claims against, the company to their knowledge.

(8) Duly authenticated copy of the list of creditors and debenture-holders showing their names, address and the amounts due to each of them shall be kept at the registered office of the company and any person desirous of inspecting the same may, at any time, during the ordinary hours of business, inspect and take extracts from the same on payment of rupees ten to the company.

(9) Where the affidavit in support of the petition and in opposition thereto and the representation, if any, of the Registrar of Companies or Regional Director, as the case may be are ready for hearing, the Bench may hear the same on a date fixed for the purpose and duly intimated to the parties by the Registrar.

(10) At the hearing of the petition, the Bench may either dispose of the petition finally or give such directions as may be necessary including directions for the filing of supplemental affidavits or completion of procedural formalities or adjourn the case.

37. Application under section 58A(9).—Every application made by the depositor under sub-section (9) of Section 58A shall be in Form No. 4 in Annexure II and shall be submitted in duplicate.

38. Petition under section 397 or 398.—A petition under section 397 or 398 shall not be withdrawn without leave of the Board, and where the petition has been presented by a member or members authorised by the Central Government under sub-section (4) of section 399, notice of the application for leave to withdraw shall be given to the Central Government.

39. Petition under section 407.—A petition under clause (b) of sub-section (1) of section 407 for leave to any of the persons mentioned therein as to be appointed or to act as the managing or other director or manager of the company, shall state whether notice of the intention to apply for such leave has been given to the Central Government and shall be accompanied by a copy of such notice.

40. Reference under section 621A.—(1) Every application for compounding of an offence shall be made by a company to the Registrar specifying clearly the nature of offence, the date or period during which the offence was committed or continued, the name and address of officers of the company who have committed the offence and the prayer made.

(2) The Registrar shall forward the application made by the company together with his comments thereon, to the Board or the Regional Director, as the case may be, within 30 days from the date of receipt of the application.

(3) Every Regional Director shall exercise the powers to compound an offence, subject to any general or special order of the Board.

41. Petition under section 2A of the Monopolies Act.—Provisions of these regulations, as regards may be, apply to the petitions made under section 2A of the Monopolies Act.

42. Reference under section 22A of the Securities Act.—Provisions of these regulations, as regards making of any reference to the Board, shall apply, mutatis mutandis, to a reference that may be made under clause (c) of sub-section (4) of section 22A of the Securities Act.

CHAPTER IV

Miscellaneous

43. Enlargement of time.—Where any period is fixed by or under these regulations, or granted by a Bench, for the doing of any act, or filing of any documents or representation, the Bench may, in its discretion, from time to time, enlarge such period, even though the period fixed by or under these regulations or granted by the Bench may have expired.

44. Saving of inherent power of the Bench.—Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Bench to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Bench.

45. Amendment of order.—Clerical or arithmetical mistakes in orders made by the Bench or errors arising therein from any accidental slip or omission may, at any time, be corrected by the Bench either of its own motion or on the application of any of the parties.

46. General power to amend.—A Bench may, at any time, and on such terms as to costs or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceeding before it; and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceeding.

47. Bench to be deemed to be a Court for certain purposes.—A Bench shall be deemed to be a Court or lawful authority for the purpose of prosecution or punishment of a person who wilfully disobeys any direction or order of such Bench.

48. Power to dispense with the requirement of the regulations.—Every Bench shall have power, for reasons to be recorded in writing, to dispense with the requirements of any of these regulations, subject to such terms and conditions as may be specified.

49. Preparation of paper book.—The Bench Officer, if it so deemed fit, may call upon the parties to prepare a paper book after completion of the pleadings.

[File No. 1/10/88-CL.V/CLB/Admn.191]

By Order of the Company Law Board,

A. M. CHAKRABORTI, Member, (Company Law Board)

Annexure-I

States/Union Territories falling under each Region

[See regulation 7 (2)]

Sl. No.	Region	States/Union Territories
1. Eastern Region		States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, West Bengal and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Mizoram.
2. Northern Region		States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Chandigarh.
3. Southern Region		States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep Islands.
4. Western Region		States of Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

Annexure-II

FORMS

FORM NO. 1

[See regulations 13 and 14]

BEFORE THE COMPANY LAW BOARD,..... PRINCIPAL BENCH/
REGION BENCH, BOMBAY/CALCUTTA/MADRAS/NEW DELHI.

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956, SECTION

OR

(Where applicable)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969, SECTION 2A

OR

(Where applicable)

THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) ACT, 1956 SECTION 22A

AND

IN THE MATTER OF

(State the name and registered office address of the company)

AND

IN THE MATTER OF.....(Petitioner)

(State the name and address of the petitioner)

OR

(Where applicable)

AB

Versus

....Petitioner(s)

CD

....Respondent(s)

Details of petition :

1. Particulars of the company, whether petitioner or not
(See regulation 16)
2. Particulars of the petitioner(s) (need not be stated where company is the petitioner)
[Name, description, father's)/husband's name, occupation, capacity, i.e. qua shareholder, qua depositor and address of the petitioner(s)]
3. Particulars of respondent(s) [need not be stated where company is the respondent/(Name, description, father's)/husband's name, occupation, capacity, i.e. qua shareholder, qua depositor and address of the respondent(s)]
4. Jurisdiction of the Bench
The petitioner declares that the subject matter of the petition is within the jurisdiction of the Bench.

5. Limitation

The petitioner further declares that the petition is within the limitation laid down in section of the Companies Act, 1956 (where applicable).

6. Facts of the case are given below :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise).

7. Matters not previously filed for pending with any other Court.

The petitioner further declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this petition has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench of the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

In case the petitioner had previously filed any application, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given.

8. Relief(s) sought.

In view of the facts mentioned in para. above, the petitioner prays for the following relief(s) :

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

9. Interim order, if any, prayed for.

Pending final decision on the petition, the petitioner seeks issue of the following interim order :

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

10. Particulars of Bank Draft evidencing payment of the fee for the petition of application made :

(i) Branch of Punjab National Bank on which drawn
(Barakhamba Road, New Delhi/Brabourne Road, Calcutta/
Mount Road, Madras/Phiroz Shah Mehta Road, Bombay)

(ii) Name of the issuing Branch of Punjab National Bank

(iii) Demand Draft No.

Date

Amount Rs.

11. List of enclosures

[See regulation 18 and Annexure III]

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature of the Petitioner.

FORM NO. 2

(See regulation 17)

Misc. Application No. of
in

Original Petition No. of

XXX

Versus

YYY

....Applicant

[(Applicant/Respondent)]

....Respondent

[(Respondent/Applicant)]

Brief facts leading to the application.
Relief or prayer.

Signature of the Applicant

Signature of the
Authorised Representative.

Place :

Date :

FORM NO. 3

(See regulation 35)

BEFORE THE COMPANY LAW BOARD,.....PRINCIPAL BENCH/REGIONAL BENCH,
BOMBAY/CALCUTTA/MADRAS/NEW DELHI.REFERENCE APPLICATION NO. of
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956/SECURITIES ACT

AND

IN THE MATTER OF SECTION.....OF THE SAID ACT.

IN THE MATTER OF
(Name and address of the Company)

AND

IN THE MATTER OF
(Name and address of the Applicant)

APPLICANT

State the name and address of the persons who should be given opportunity of being
heard in disposing of this reference.(Note : Please enclose as many additional copies of the reference application as there are persons as abovenamed. This
is without prejudice to the requirements of sub-regulation (1) of regulation 41).

On the basis of the information available from the documents annexed hereto—

1. The applicant hereby makes reference to the Company Law Board,.....Principal Bench/Regional
Bench,, under sectionof the Companies Act, 1956/Securities Act. (Here state the
nature of reference).2. The applicant states as follows :
(Here set out the brief facts of the case).3. The submissions of the applicant are as follows :
(Submissions).

4. The applicant has annexed hereto the documents or copies thereof as specified below :

5. The applicant is seeking specified order of the Company Law Board (Here specify the nature of the order sought for).

Signature of the applicant.

Place :

Date :

List of Documents :

- 1.
- 2.
- 3.

FORM NO.

(See Regulation 37)

Application by depositor under section 58A (9)

Before the Company Law Board (.....Bench) In the matter of the Companies Act, 1956 (1
of 1956)

Section 58A

And

In the matter of (State the name of the Depositor-applicant)

and

In the matter of.....Limited (State the name of the company).

(i) Name and address of the Depositor-applicant :

(ii) Name of the company and address of its Registered Office :

(iii) Name(s) of Depositor(s) with full address :

(iv) Amount of Deposit :

(v) Fixed Deposit Receipt No. & Date
(Photostat copy to be enclosed).

(vi) Terms and Conditions of Deposit as also date of Maturity of Deposit :

(vii) Details of payment made, by the company, if any :

(viii) Actual amount due as on date of application (Principal/interest) :

(ix) Details of correspondence, if any, made between the company and the
Depositor (copy of correspondence to be enclosed) :

(x) Any other particular(s) as may be considered relevant :

The Depositor-applicant, therefore, prays :—

- (i) that the company, above-named be directed to make repayment of the aforesaid Deposit(s) alongwith interest due thereon in accordance with the Terms and Conditions of the Deposit;
- (ii) that such further orders be passed as the Company Law Board may deem fit in the circumstances of the case.

(Signature of the Depositor-applicant)

Place

Date

Notes :

1. The application shall be accompanied by a fee of Rupees Fifty by way of Bank Draft in favour of "The Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi/Bombay/Calcutta/Madras".
2. This application shall be made in duplicate.

Annexure-III

Documents to be attached with a petition

(See regulations 18 and 34)

Sl. No.	Section of the Act	Nature of petition	Enclosures to petition
1	2	3	4
1.	17(2)	Petition for confirming alteration in Memorandum of Association as to change of place of the registered office from one State to another or with respect to objects of a company.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the memorandum and articles of association. 2. Copy of the notice calling for the meeting with Explanatory Statement. 3. Copy of the Special Resolution sanctioning the alteration by the members of the company. 4. Copy of the minutes of the meeting at which the Special Resolution was passed. 5. Affidavit verifying the petition. 6. Bank draft evidencing payment of application fee. 7. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution of the executed Vakalatnama, as the case may be. Copy of the latest audited balance sheet with the profit and loss account of the company with auditor's report and directors' report. 9. Affidavit proving despatch and service of notice together with newspaper cuttings. 10. Affidavit verifying list of creditors as per regulation 36 (7). 11. Acknowledgement receipts from the Registrar of Companies/Regional Director and/or from the Chief Secretary of the State Government/Administrator, where applicable (See regulation 14(3)).
2.	18(4)	Application for extension of time for filing documents for registration of alteration.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Application supported by affidavit. 2. Bank draft evidencing payment of application fee.
3.	19	Application for revival of order made under Section 17.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Application duly supported by affidavit. 2. Bank draft evidencing payment of application fee.

1	2	3	4
4. 43	Petition praying for relief from consequences of failure to comply with conditions constituting it a private company.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the memorandum and articles of association. 2. Copy of the documents showing that the default has been committed in complying with the conditions laid down in clause (iii) of subsection (1) of section 3. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Bank draft evidencing payment of application fee. 5. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
5. 49(10)	Petition to direct the company to allow an immediate inspection of Register of Investments, if the inspection is refused.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence, if any, showing the refusal on the part of the company to allow inspection of the Register of Investments. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 5. Any other relevant correspondence exchanged in the matter with the company. 6. Acknowledgement receipt from the Registrar of Companies (See Regulation 14(4)).
6. 58A (9)	Petition to direct the company to make repayment of the matured deposits.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the deposit receipt. 2. Copy of the correspondence exchanged with the company. 3. Bank Draft evidencing payment of application fee.
7. 79 (2)	Petition to sanction issue of shares at a discount.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the memorandum and articles of association. 2. Copy of the notice calling for the meeting with Explanatory Statement and the Resolution sanctioning issue. 3. Copy of the minutes of the meeting at which the resolution was passed. 4. Copies of the last three years audited balance sheets and profit and loss accounts, auditor's reports and directors' reports. 5. Affidavit verifying the petition. 6. Bank draft evidencing payment of application fee. 7. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
8. 89A (1) Proviso	Petition to give consent to the issue of further redeemable preference shares in lieu of irredeemable preference shares.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the memorandum and articles of association. 2. Documents showing the terms of issue of the existing preference shares. 3. Copy of the Board Resolution and resolution of general meeting for issue of further redeemable preference shares.

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Copy of the latest audited balance sheet and profit and loss account of the company with auditors' report and directors' report. 5. Affidavit verifying the petition. 6. Bank draft evidencing payment of application fee. 7. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
			Where the Company is the petitioner
9. 111	Petition for rectification of Register of Members on any ground including refusal of registration of transfer/transmission of shares/debentures by the company.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the memorandum and articles of association. 2. Latest audited balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report. 3. Authenticated copy of the extract of the Register of Members. 4. Copy of the resolution of the Board or Committee of Directors (where applicable). 5. Any other relevant documents. 6. Affidavit verifying the petition. 7. Bank draft evidencing payment of application fee. 8. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 9. Two extra copies of the petition.
			Where the petition is made by any other person :
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence in support of the Statements made in the petition including the copy of the letter written by the petitioner to the company for the purpose of registering the transfer of, or the transmission of the right to any shares or interest in, or debentures as also a copy of the letter of refusal of the company. 2. Copies of the documents returned by the company. 3. Any other relevant documents. 4. Affidavit verifying the petition. 5. Bank draft evidencing payment of application fee. 6. Memorandum of appearance with copy of the executed Vakalatnama. 7. Two extra copies of the petition.
10. 113(1)	Petition for extending the period for delivery of the certificates of debentures.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the letter of allotment issued by the company. 2. Copy of the instrument of transfer, if any. 3. Copies of the resolution of the Board allowing the transfer and/or seeking extension. 4. Affidavit verifying the petition. 5. Bank draft evidencing payment of application fee. 6. Copy of the latest audited balance sheet and profit and loss account together with auditor's report and director's report. 7. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.

1	2	3	4
11. 113(3)	Petition for non-compliance of sub-section (1) of Section 113 providing time limit for issue of share/debenture certificates.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the letter of allotment issued by the company. 2. Documentary evidence for the lodgment of shares or debentures for transfer, if any. 3. Copy of the notice served on the company requiring it to make good the default in complying with the requirement under sub-section (1) of Section 113. 4. Any other correspondence. 5. Affidavit verifying the petition. 6. Bank draft evidencing payment of application fee. 7. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
12. 118(3)	Petition for furnishing copy of trust deed to person requiring it.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the letter written to the company for the issue of trust deed. 2. Copy of the letter of refusal if any, issued by the company. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Bank draft evidencing payment of application fee. 5. Memorandum of appearance with the copy of the executed Vakalatnama.
13. 141(1) and (3)	Petition for extension of time or condonation of delay in filing the particulars of a charge or modification of a charge or limitation of payment or satisfaction of a charge with the Registrar of Companies.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Copy of the agreement creating, modifying the charge, as the case may be. 2. Copy of the resolution envisaged by Section 292(1)(b) or (c) and Section 293(1)(a), as may be applicable. 3. Affidavit along with newspaper cuttings. 4. Affidavit verifying the petition. 5. Bank draft evidencing payment of application fee. 6. Memorandum of appearance with copy of Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
14. 144(4)	Petition to direct inspection of copies of instrument creating charge or register of charges.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with the copy of the executed Vakalatnama.
15. 163(6)	Petition to direct inspection of registers and returns or to furnish the copies thereof to the person requiring it.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with the copy of the executed Vakalatnama.
16. 167	Application for directing to call annual general meeting.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Affidavit verifying the application. 2. Bank draft evidencing payment of application fee.
17. 186	Application for ordering for calling of general meeting (other than annual general meeting).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary Evidence in proof of status of the applicant. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with the copy of the executed Vakalatnama.

1	2	3	4
18. 188(5)	Application for order as to whether the rights conferred are being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order company's costs to be paid in whole or in part by the requisitionists.		1. Affidavit verifying the petition. 2. Bank draft evidencing payment of application fee. 3. Memorandum of appearance or duly executed Vakalatnama.
19. 196(4)	Petition to pass an order directing immediate inspection of minute books or directing a copy thereof be sent forthwith to person requiring it.		1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
20. 219(4)	Petition to pass an order directing that a copy of balance sheet and auditor's report demanded be furnished forthwith to person concerned.		1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
21. 225(3) Proviso	Petition to decide as to whether right of auditors to get their representation circulated and read out at meeting is being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order an application to be paid in whole or in part by retiring auditors.		1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
22. 235(2)	Petition to declare by an order that affairs of a company be investigated by inspector(s).		1. Documentary and/or other evidence in support of the statements made in the petition, as are reasonably open to the petitioner(s). 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Bank draft evidencing payment of application fee. 5. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 6. Three extra copies of the petition.
23. 250	Complaint by any person for finding out facts about certain shares.		1. Documentary evidence, if any, in support of the complaint. 2. Affidavit verifying the complaint. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance.
24. 284(4) proviso	Petition to decide as to whether the right of a director to get his representation circulated and read out at meeting is being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order company's costs on application to be paid in whole or in part by such director.		1. Documentary evidence, if any, petition showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.

1	2	3	4
25. 304(2)(b)	Petition to pass an order directing immediate inspection of register maintained under Section 303.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
26. 307(9)	Petition to pass an order directing immediate inspection of register maintained under the section.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary evidence, if any, showing the refusal of the company to give inspection to the petitioner. 2. Affidavit verifying the petition. 3. Bank draft evidencing payment of application fee. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution of the executed Vakalatnama, as the case may be.
27. 397, 398, 399(4), 400, 401, 402, 403, 404, 405.	Petition to exercise powers in connection with prevention of oppression and/or mismanagement.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Document and/or other evidence in support of the statements made in the petition, as are reasonably open to the petitioner(s). 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them. 3. Where the petition is presented on behalf of members, the letter of consent given by them. 4. Statement of particulars showing names, addresses, number of shares held and whether all calls and other monies due on shares have been paid in respect of members who have given consent to the petition being presented on their behalf. 5. Where the petition is presented by any member or members authorised by the Central Government under section 399(4) the order of the Central Government authorising such member or members to present the petition shall be similarly annexed to the petition. 6. Affidavit verifying the petition. 7. Bank draft evidencing payment of application fee. 8. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 9. Three spare copies of the petition.
28. 407(1)(b)	Petition to grant leave for an appointment of Managing Director or manager whose agreement has been terminated or set aside provided notice has been served on Central Government.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentary and/or other evidence in support of the statements made in the petition, as are reasonably open to the petitioner(s). 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them. 3. Where the petition is presented on behalf of members, the letter of consent given by them. 4. Statement of particulars showing names, addresses, number of shares held and whether all calls and other monies due on shares have been paid in respect of members who have given consent to the petition being presented on their behalf. 5. Whether the petition is presented by any member or members authorised by the Central Government under section 399(4), the order of the Central Government authorising such member or members to present the petition shall be similarly annexed to the petition.

1	2	3	4
			6. Affidavit verifying the petition. 7. Bank draft evidencing payment of application fee. 8. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be.
29. 408(1), (2) and (5)	Petition to decide whether it is necessary to appoint Government directors on the Board of directors and to advise Central Government accordingly.		1. Documentary and/or other evidence in support of the statements made in the petition as are reasonably open to the petitioner(s). 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Bank draft evidencing payment of application fee. 5. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 6. Three spare copies of the petition.
30. 409(1)	Petition to prevent change in Board of Directors likely to affect company prejudicially.		1. Documentary and/or other evidence in support of the statements made in the petition, as are reasonably open to the petitioner(s). 2. Documentary evidence in proof of the eligibility and status of the petitioner(s) with the voting power held by each of them. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Bank draft evidencing payment of application fee. 5. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama as the case may be. 6. Three extra copies of the petition.
31. 614(1)	Petition to pass an order directing a company to make good the default from its failure to make returns etc. to the Registrar of Companies.		1. Copy of the notice served on the company to make good the default. 2. Documentary evidence as to the service of notice. 3. Affidavit verifying the petition. 4. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or the executed Vakalatnama, as the case may be. 5. Bank draft evidencing payment of application fee.
32. 22A(4)(C) of the Securities Act.	Reference to issue of direction for registration/non-registration of securities.		1. Instrument of transfer and other documents accompanying the transfer lodged with the company. 2. Copies of correspondence exchanged with the transferor/transferee/Stock broker/concerned stock exchange. 3. Authenticated copy of the lodgment of instrument of transfer with the company. 4. Notice given to the transferor/transferee under clause (b) of sub-section (4) of Section 22A of the Securities Act. 5. Resolution of the Board of directors giving reasons for refusal to register the transfers. 6. Three copies of the memorandum and articles of association and latest audited balance sheet and profit and loss account of the company. 7. Affidavit verifying the petition.

1	2	3	4
			8. Bank draft evidencing payment of application fee.
			9. Memorandum of appearance with copy of the Board Resolution or executed Vakalatnama.
			10. Two extra copies of reference.
33. 2A of the Monopolies Act.	Petition for determination of any question of group interconnection or same management in accordance with the provisions of Section 2A of the Monopolies Act.		1. Documentary evidence in of the statements made in the petition, as are reasonably open to the petitioner(s).
			2. Affidavit verifying the petition.
			3. Bank draft evidencing payment of application fee.
			4. Three extra copies of the petition.

Note : Copy of each document, as specified above, should be authenticated or certified to be true copy.

